



संक्षिप्तवार्ता

अदालत 14 अक्टूबर को सुनाएगा फैसला

भोपाल। सिंधिया राजघराने की 40 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति के विवाद के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय में संपत्ति विवाद में पेश किए गए अंतरिम आवेदनों पर बहस पूरी हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ पद्मावती राजे की बेटी प्रतिमा देवी की ओर से प्रस्तुत आवेदन को न्यायालय ने पिछली सुनवाई में स्वीकार कर लिया था। इसी आपत्ति पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस हुई। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 14 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य की बड़ी बुआ की बेटी प्रतिमा देवी ने सहमति से हुए बंटवारे का विरोध किया। प्रतिमा देवी का तर्क है कि बंटवारे पर जो हस्ताक्षर बचाए जा रहे हैं, वोखे से कराए गए हैं। इसके लिए साक्ष्य कराए जाएं। उषा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे ने विरोध करते हुए कहा कि हस्ताक्षर सहमति से हुए हैं। हस्ताक्षर के बाद परिवार का डिनर भी हुआ था।

मध्य प्रदेश में पटवारियों का 3 दिन सामूहिक अवकाश

भोपाल। मध्यप्रदेश में पटवारी गुरुवार से 3 दिन तक सामूहिक अवकाश पर हैं। इस दौरान स्वामित्व योजना और राजस्व कार्य में कार्रवाई का विरोध करेंगे। प्रदेश में अब तक दो दर्जन से ज्यादा पटवारियों की सेवा समाप्त हुई है। कार्रवाई वापस नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं पटवारियों के अवकाश से राजस्व कार्य प्रभावित होगा। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 को लेकर पटवारियों पर हो रही निवेदन, सेवा समाप्ति और अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों के विरोध में मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ के आह्वान पर पटवारियों ने सभी ऑनलाइन राजस्व कार्य पूरी तरह बंद कर दिए हैं। संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि पटवारियों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई वापस नहीं ली जाती है, तो गुरुवार से सभी पटवारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। देवास में तीन पटवारियों की सेवा समाप्त करने का कड़ा विरोध करते हुए जिला अध्यक्ष देवेन्द्र कदम और इटारसी तहसील अध्यक्ष देवीशरण पटेल ने बताया कि राज्यभर में पटवारियों पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। संघ का कहना है कि स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक और कानूनी अड़चनों से सरकार को पहले ही अवगत कराया जा चुका है।

कंगना रनौत ने अपनी तस्वीर, आवाज के गलत इस्तेमाल पर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

नई दिल्ली। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने नाम, तस्वीर, शवल-सूरत और व्यक्तिव से जुड़ी अन्य विशेषताओं के कथित अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ अपने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की है। जस्टिस विकास महाजन गुरुवार को इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी और वर्तमान में सांसद कंगना ने अपनी पहचान और व्यक्तिव के कथित अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल को रोकने के लिए कोर्ट से दखल की मांग की है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पर्सनैलिटी राइट्स मोटे तौर पर किसी व्यक्ति के नाम, तस्वीर, आवाज, शवल-सूरत, हस्ताक्षर



और अन्य खास विशेषताओं को अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल से बचाते हैं। भारतीय अदालतों ने ऐसे अधिकारों को मान्यता दी है, खासकर उन मामलों में जिनमें एक्टर और

अन्य महशूर हस्तियां शामिल हैं। कोर्ट ने अन्य लोगों के अलावा, अभिनेता अमिताभ बच्चन के पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की रक्षा करते हुए उनके नाम,

तस्वीर, आवाज और शवल-सूरत के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाई है।

एक्टर अनिल कपूर के मामले में भी, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ी विशेषताओं - जिसमें उनका नाम, तस्वीर, शवल-सूरत, आवाज और खास अंदाज शामिल हैं - गलत इस्तेमाल के खिलाफ सुरक्षा दी और संस्थाओं को बिना अनुमति के इन विशेषताओं का इस्तेमाल करने से रोका। इसी तरह, कोर्ट ने रजनीकांत, जैकी श्रॉफ, अजिंथी सिंह जैसे एक्टर के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए आदेश पारित किए हैं, जिनमें उनकी पहचान या व्यक्तिव के कथित अनधिकृत इस्तेमाल से जुड़े अलग-अलग मामले शामिल थे।

अनोखे अंदाज और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर

टाइम्स ऑफ पीडीया

98 हजार परिवारों के एलपीजी कनेक्शन बंद

केवाईसी की कार्रवाई और पीएनजी रिकॉर्ड ने हजारों एलपीजी उपभोक्ताओं को फंसाया

भोपाल। राजधानी में रसोई गैस का संकट सिर्फ ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है। करीब 98 हजार परिवारों के एलपीजी कनेक्शन अलग-अलग कारणों से बांद होने से उनकी रसोई प्रभावित हो रही है। इनमें करीब 83 हजार कनेक्शन ई-केवाईसी नहीं होने के कारण बंद किए गए हैं, जबकि 30 से अधिक कॉलोनियों में करीब 14 से 15 हजार कनेक्शन पीएनजी उपलब्ध होने के रिकॉर्ड के आधार पर ब्लॉक किए गए हैं।

सबसे बड़ी परेशानी उन उपभोक्ताओं के सामने है, जिनके क्षेत्र में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध बताई जा रही है, लेकिन वास्तव में या तो पाइपलाइन पहुंची ही नहीं है या घरों को अब तक पीएनजी कनेक्शन नहीं मिला है। ऐसे उपभोक्ताओं की एलपीजी बुकिंग भी बंद हो गई है। नतीजतन लोग गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं और कनेक्शन दोबारा चालू कराने की कोशिश कर रहे हैं।

83 हजार कनेक्शन ई-केवाईसी

सीजेपी के 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर पूरी दिल्ली किले में तब्दील

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांफेंचर जनता पार्टी (सीजेपी) ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर दिए गए विरोध प्रदर्शन के आह्वान ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर ला दिया है। दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की औपचारिक अनुमति नहीं दी है, लेकिन सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिग्ग के कड़े रुख और हजारों समर्थकों के जुटने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सभी स्टेशन हाउस ऑफिसर्स को अपने-अपने इलाकों में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। पुलिस उन लोगों पर विशेष निगरानी रख रही है जो पहले गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं। पुलिस टीम यह पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली कौन आ सकता है और वे किन जगहों से आ रहे हैं। दिल्ली की ओर बसों की आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों को दिल्ली की ओर जाने वाली बसों के बारे में जानकारी ट्रैक करने और निगरानी और कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस टीमों को सतर्क करने का निर्देश दिया है।



रिकॉर्ड में पीएनजी, जमीन पर सुविधा नहीं

शहर की कई कॉलोनियों में पीएनजी लाइन बिछाने का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन हर घर तक कनेक्शन पहुंचने की स्थिति अलग है। कुछ इलाकों में पाइपलाइन ही नहीं है, जबकि कुछ जगह लाइन होने के बावजूद उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन नहीं मिला है। इसके बावजूद इन उपभोक्ताओं के एलपीजी कनेक्शन ब्लॉक होने से उन्हें सिलिंडर बुक कराने में परेशानी हो रही है। इससे उपभोक्ताओं के सामने सवाल यह है कि जब पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो केवल रिकॉर्ड के आधार पर एलपीजी सुविधा क्यों बंद की जा रही है।

के कारण बंद

इसके अलावा भोपाल में करीब 83 हजार एलपीजी कनेक्शन ई-केवाईसी नहीं होने के कारण बंद किए गए हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद ही कनेक्शन

को सामान्य स्थिति में लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन ब्लॉक है, वे संबंधित गैस एजेंसी में अपना नंबर देकर इसका कारण पता कर सकते हैं। यदि पीएनजी उपलब्ध

नहीं होने के बावजूद कनेक्शन ब्लॉक हुआ है तो उपभोक्ता लिखित शिकायत देकर दोबारा ई-केवाईसी करा सकते हैं। समाधान नहीं होने पर संबंधित गैस कंपनी की वेबसाइट या टोल फ्री नंबर पर शिकायत की जा सकती है।

त्योहार के समय बढ़ी परेशानी

दीपावली के आसपास रसोई गैस की जरूरत बढ़ने के बीच इतने बड़े पैमाने पर कनेक्शन बंद होने से उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ गई है। खासकर उन परिवारों के लिए स्थिति ज्यादा मुश्किल है, जिनके पास पीएनजी का विकल्प मौजूद नहीं है और एलपीजी कनेक्शन भी ब्लॉक हो चुका है। अब चुनौती यह है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराने के साथ उन उपभोक्ताओं के कनेक्शन की भी अलग से जांच हो, जिनका एलपीजी कनेक्शन पीएनजी उपलब्ध होने के रिकॉर्ड के आधार पर बंद किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि वास्तव में कितने घरों में पीएनजी पहुंच चुकी है और कितने परिवार अभी भी पूरी तरह एलपीजी पर निर्भर हैं।

पीएम मोदी बोले- उन्होंने ऐसे पात्र निभाए, जिन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा

इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में भारत के डिजिटल बदलाव, मोबाइल कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा और तकनीकी विकास पर विस्तार से बात की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मोबाइल और इंटरनेट अब केवल संचार का माध्यम नहीं रह गए हैं, बल्कि सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान की व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। पहले बैंक, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों तक पहुंच के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन आज सरकार की सैकड़ों सेवाएं मोबाइल के जरिए उपलब्ध हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुंच रही है। उन्होंने दावा किया कि इससे करीब पांच लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक करीब चार लाख करोड़ रुपये किसानों के खातों में पहुंचाए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन और नेटवर्क की सुरक्षा आज बड़ी प्राथमिकता है।



स्टेकल विदाउट बाउंड्रीज है थीन

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की थीम स्केल विदाउट बाउंड्रीज यानी बिना सीमाओं के विस्तार रखी गई है। आयोजन में 5जी-6जी, एआई नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, सैटेलाइट नेटवर्क, साइबर सुरक्षा और क्वांटम कम्युनिकेशन जैसी तकनीकों पर चर्चा होगी। स्मार्ट मॉबिलिटी, स्टेडियम अनुभव, औद्योगिक रोबोटिक्स और परिवहन तकनीक जैसे नए क्षेत्रों को भी इस बार आयोजन में प्रमुखता दी गई है।

आम नागरिक को यह भरोसा होना चाहिए कि फोन करने वाला कौन है, उसका भुगतान सुरक्षित है और उसका डेटा भी सुरक्षित है।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराध सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। एक देश में बैठा अपराधी दूसरे देश को मदद से तीसरे देश में साइबर अपराध कर सकता है। ऐसे में साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रभावी फ्रेमवर्क तैयार

कितना भी कठिन समय आए, कमजोर कड़ी नहीं बनना: वायुसेना प्रमुख

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना ने गुरुवार को अपना 94वां वायुसेना दिवस मनाया। इस अवसर पर गजियाबाद स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन में भव्य परेड आयोजित की गई। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, थलसेना प्रमुख जनरल वीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, पूर्व वायुसेना प्रमुख, वायु योद्धाओं और विशिष्ट अतिथियों ने हिस्सा लिया।

वायुसेना दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा कि हर वायु योद्धा को यह संकल्प लेना चाहिए कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आए, वह ऐसी कमजोर कड़ी नहीं बनेगा, जिससे वायुसेना रुपी श्रृंखला कमजोर या टूट जाए। उन्होंने कहा कि वायुसेना का प्रत्येक सदस्य संगठन की महत्वपूर्ण कड़ी है और उसे अपने कर्तव्यों



व जिम्मेदारियों पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने वायुसेना में आपसी सम्मान और समानता का वातावरण बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन में किसी भी तरह का पक्षपात या भेदभाव नहीं होना चाहिए। वायु योद्धाओं को संगठन के हित को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखने का आह्वान करते हुए उन्होंने स्वयं से पहले सेवा के सिद्धांत को वायुसेना के मूल भाव के रूप में रेखांकित किया।

एसआईआर के खिलाफ बेंगलुरु में चप्पल प्रदर्शन

बेंगलुरु। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में गुरुवार को कांफेंचर जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से चप्पल प्रदर्शन किया गया। इससे पहले यहां एसआईआर को लेकर जनता न्यायाधिकरण आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसआईआर प्रक्रिया से कथित तौर पर प्रभावित लोगों ने अपनी शिकायतें और अनुभव सामने रखे।

सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका के मुताबिक, चप्पल प्रदर्शन का उद्देश्य उन लोगों की ओर ध्यान आकर्षित करना था, जिनके नाम कथित तौर पर एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए। आयोजकों का दावा है कि जनता न्यायाधिकरण में कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों से ऐसे लोग शामिल हुए, जो खुद को एसआईआर से प्रभावित बता रहे हैं।

करने की जरूरत है।

शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच आसान

पीएम मोदी ने कहा कि मोबाइल-इंटरनेट कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान को दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौविड काल के दौरान दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 2022 तक 500 करोड़ से अधिक लर्निंग सेशन दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यमों से गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चों को भी जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत में मोबाइल फोन और दूरसंचार उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा दिया गया है। इससे तकनीकी की पहुंच बढ़ी और लोगों के लिए डिजिटल सेवाएं अधिक सुलभ हुईं।

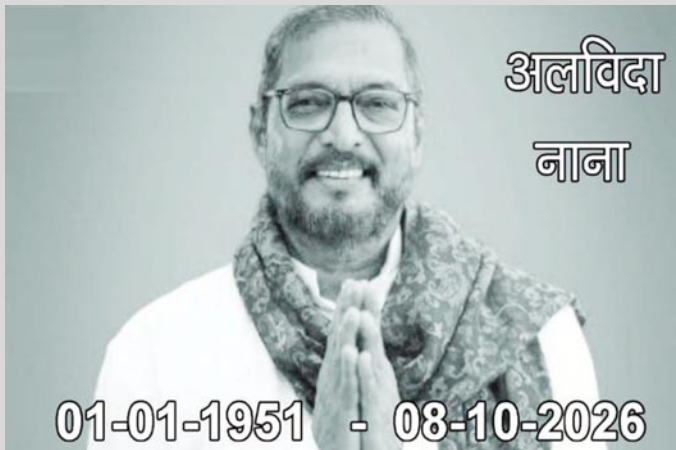
25 साल की सार्वजनिक सेवा का किया जिक्र

पीएम मोदी ने कहा कि देश की सेवा करते हुए उनके 25 वर्ष पूरे हुए हैं और इसके लिए उन्होंने देशवासियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह संयोग है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस के भी 10 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने नाना पाटेकर के निधन पर भी शोक व्यक्त किया और उन्हें बेहतरीन कलाकार बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में विशेष स्थान बनाया।

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की आयु में निधन, गंभीर कार्डियक अरेस्ट : गोवा में ली अंतिम सांस

गोवा। हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह उनके गोवा स्थित आवास पर निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 75 वर्षीय अभिनेता को गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया।

हालांकि, तमाम प्रयासों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और सुबह करीब 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मणिपाल अस्पताल के अंतर्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर ने बताया कि नाना पाटेकर को गंभीर कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उनकी जान बचाने के लिए करीब 45



01-01-1951 - 08-10-2026

मिनट तक लगातार सीपीआर दिया गया। इसके बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। डॉक्टर के मुताबिक, इस मामले में मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) दर्ज किया गया है और

नाना पाटेकर के निधन की चिकित्सकीय वजह की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

नाना पाटेकर के निधन की खबर सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों के बीच शोक की लहर

है। उनका फिल्मी सफर चार दशक से भी ज्यादा लंबा रहा, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1978 में फिल्म गमन से की थी। अपने अभिनय से उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में एक विशिष्ट पहचान बनाई।

सम्मानित किया था

परिदा, अंगार, तिरंगा, क्रांतिवीर, अग्निप्राणी, अब तक छप्पन, अपहरण, वेलकम और नटसम्राट जैसी फिल्मों में उनके दमदार अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा। फिल्म क्रांतिवीर में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपने करियर में उन्होंने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ कई फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते। भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया था।

नाना पाटेकर के निधन से फिल्म जगत और राजनीति में शोक की लहर, कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से फिल्म जगत के साथ राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर दौड़ गई। 75 वर्षीय नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह गोवा स्थित अपने आवास पर गंभीर कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया। मणिपाल अस्पताल के डॉ. शेखर सालकर के मुताबिक, नाना को बचाने के लिए करीब 45 मिनट तक सीपीआर दिया गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

नाना पाटेकर के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र और विभिन्न राज्यों के कई नेताओं ने शोक जताया। पीएम मोदी ने नाना को याद करते हुए कहा कि उनमें जबरदस्त जोश, अनोखापन और दमदार मौजूदगी थी। उन्होंने अपने हर किरदार में विविधता और रचनात्मकता दिखाई। उन्होंने अपने हर किरदार में शानदार विविधता और रचनात्मकता दिखाई और ऐसे पात्र निभाए, जिन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। पीएम ने कहा कि नाना अपने बेबाक

और स्पष्ट विचारों के लिए भी जाने जाते थे। हिंदी और मराठी सिनेमा में उनका योगदान बेहद बड़ा था और उनके निधन से कला जगत में बड़ी कमी पैदा हुई है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाना पाटेकर के निधन को कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि नाना ने अपनी शानदार अदाकारी से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया और सामाजिक सरोकारों के जरिए समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाना के निधन पर गहरा दुख जताते हुए उन्हें अपना करीबी दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि नाना ने मराठी और हिंदी सिनेमा को एक पूरा दौं दिया। क्रांतिवीर, परिदा और नटसम्राट जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को हमेशा याद किया जाएगा। फडणवीस ने नाना के सामाजिक कार्यों का भी उल्लेख किया और कहा कि किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को मदद के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया।

संपादकीय आकाशवाणी बना जंतर-मंतर

विपक्ष के इंडी गठबंधन ने सेव डेमोक्रेसी मार्च निकाला, लेकिन वह हजूम के अलावा कुछ भी साबित नहीं हुआ। अंततः विरोध-प्रदर्शन बजर ही रहा। यदि विपक्ष को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और दो चुनाव आयुक्तों से मिल कर अपना ज्ञापन सौंपना था, तो संवैधानिक संस्था के प्रोटोकॉल के मुताबिक, समय मांगना चाहिए था। करीब 200 या 300 सांसद एकसाथ चुनाव आयोग में न तो जा सकते हैं और न ही कोई सार्थक संवाद संभव है, लिहाजा विपक्ष के 5-7 नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल तय किया जाना चाहिए था, जो चुनाव आयोग में संवाद कर सकता था। बैरिकेड्स पर चढ़ना, अपनी पहलवानी मुद्राएं दिखाना और अनाप-शनाप नारेबाजी करने से न तो सताएं घबरती हैं और न ही सीईसी ज्ञानेश कुमार गुप्ता डर कर इस्तीफा दे सकते हैं। उन्हें भी सविधान का संरक्षण हासिल है। सवाल आंदोलन की नीयत और हजूम की अराजकता का भी है। जब विपक्ष को चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च करना था, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनकी सांसद बहन वैष्णवीपाल, और कुछ पिछलग्गू कांग्रेसी सांसद अचानक आकाशवाणी भवन में क्यों घुस गए? वहां सरकारी दमतर हैं, जो कामकाज करते रहते हैं। उन्हें बाधा पहुंचाना भी दंडनीय अपराध है। कांग्रेस गच्चा देकर चुनाव आयोग तक पहुंचने का उद्देश्य भी रणनीति खेल रही होगी, क्योंकि आकाशवाणी के पिछले दरवाजे से आयोग का मुख्य दरवाजा कुछ मीटर के फासले पर ही था, लेकिन सुरक्षा-व्यवस्था अपेक्षाकृत ज्यादा चौकनी होती है।

वह दरवाजा स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। अंततः राहुल गांधी और सहयोगी प्रदर्शनकारियों को हार कर, आकाशवाणी भवन के भीतर ही, बरगद के पुराने पेड़ की छाया में, कथित धरना देना पड़ा। यह नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद के प्रति सम्मान का भाव ही था कि पुलिस अधिकारी और बाद मेंगृह मंत्रालयके आला अफसरोंने राहुल गांधी को समझाया कि आकाशवाणी भवन जंतर-मंतर नहीं है। धरने-प्रदर्शन का अधिकृत स्थान नहीं है, लिहाजा उन्हें धरना समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन राहुल, प्रियंका, वैष्णवीपाल, दीपेन्द्र हुड्डा, पवन खेड़ा आदि कांग्रेसी सांसद करीब 9 घंटे तक पेड़ के नीचे बैठे रहे। वही खाना-पीना जारी रहा। यह कैसा विरोध-प्रदर्शन था! नारेबाजी भी थक कर खामोश हो चुकी थी। सांसद अलसा रहे थे। अंततः गृह मंत्रालय के शीर्ष आदेशों के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरन उठाया और हिरासत में लेकर किसिव्ते कैप पुलिस लाइन भेज दिया। रात्रि करीब 10 बजे सभी को मुक्त भी कर दिया गया। क्या हासिल हुआ? क्या ऐसे हजूम से चुनाव आयोग घुटने टेक सकता है? क्या करोड़ों मतदाताओं को उनका मताधिकार बहाल कराया जा सकता है? दिन भर के नाटक का तो पक्षोपेय हो गया, उसी दौरान कुछ पुराने वीीडियो टीवी चैनलों पर दिखाई दिए। उनमें राहुल गांधी, राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट आदि डुलीकेट और फर्जी मतदाताओं की शिकायत कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि शररु भी बयान दे चुके हैं कि केरलम में मतदाता सूचियों से फर्जी नाम काट कर कायदा पाटीं को मिला और सरकार बन सकी। वीडियो में कांग्रेसी नेता डुलीकेट नामों को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। अब चुनाव आयोग के अभियान में कई विसंगतियां, गलतियां, लापरवाहियां सामने आई हैं, लेकिन अब मामला सर्वोच्च अदालत के विचाराधीन है। कमबोश्त उसे न्याय करे देा। अदालत का न्याय भी उचित न लगे, तो आंदोलन का रास्ता तो हमेशा खुला है। एक और ऐतिहासिक तथ्य सामने रखने का मन कर रहा है। यदि तमिलनाडु में 1967 से, बंगाल में 1977 से, उप्र में 1989 से, गुजरात में 1995 से और ओडिशा में 2005 से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो ये वोट चोरी के नतीजतन नहीं हैं। जनता ने उसे खारिज किया है, लिहाजा जनमत लगातन कांग्रेस के खिलाफ रहा है। कांग्रेस करीब 280 लोकसभा सीटों के समान क्षेत्रों में शून्य हो चुकी है। यह शून्यता चुनाव आयोग के किसी अभियान की वजह से नहीं है, लिहाजा कांग्रेस को देश के ज्वलंत मुद्दों पर भी सड़कों पर बिछ जाना चाहिए। यह भी लगे-सरोकार का मुद्दा है, लेकिन इसे गंभीरता और कानूनी दायरे में रह कर लेना चाहिए। आंदोलन में जनता को संघर्षातित करना चाहिए। अलबत्ता हजूम इकं करते रहिए, नतीजा बहुत अस्ख मिलना बेहद मुश्किल है। हमारा मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है, इसलिए कांग्रेस को मजबूत किया जाना चाहिए।

लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जनता का विश्वास

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी चुनाव प्रणाली और जनता का मताधिकार है। सत्ता बदलने का अधिकार जनता के पास है और इसी अधिकार की विश्वसनीयता लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करती है। लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगें, मतदाता सूची की शुद्धिता को लेकर संदेह पैदा होे और विपक्ष चुनाव प्रणाली में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए सड़क पर उतर आए, तो यह केवल किसी राजनीतिक दल का विरोध नहीं रह जाता, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन जाता है। इसलिए लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है जनता का विश्वास है। अगर यह विश्वास खो गया तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही खो जायेगा? इस पर लोकतंत्र के चौकीदारों को सोचा पड़ेगा समझना पड़ेगा? जनता के अंदर यह विश्वास दिलाना होगा कि आपका वोट सुरक्षित है।

राजधानी दिल्ली में मंगलवार को जो राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, उसने इस बहस को और तेज कर दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इडिया गठबंधन के मार्च की धुरी बने और विपक्षी सांसद संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर ही रोक दिया। इसके बाद सड़क पर धरना, हिरासत और फिर आकाशवाणी भवन परिसर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड़ा तथा अन्य नेताओं का करीब नौ घंटे तक चला विरोध प्रदर्शन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में सामने आया। राहुल गांधी की हिरासत और उनके साथ बड़ी संख्या में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी ने राजनीतिक टकराव को और तीखा कर दिया। दर रत सभी को छोड़ दिया गया, लेकिन इस घटनाक्रम ने एक बुनियादी सवाल जरूर खड़ा किया है। क्या चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान राजनीतिक टकराव से होगा या संस्थागत संवाद से? विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची और चुनाव प्रणाली में ऐसी अनियमितताएँ हो रही हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए तथा वोट चोरी के जरिए देश को हाईजैक करने तक की बात कही। उन्होंने इसे देशद्रोह बताया और कहा कि ऐसा करने वाले बच नहीं पाएंगे। इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इनका राजनीतिक भाषणों तक सीमित रह जाना उचित नहीं होगा। यदि आरोप गलत हैं तो उन्हें तथ्यों के साथ खारिज किया जाना चाहिए और यदि किसी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के प्रमाण हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र में आरोप और प्रत्यारोप से अधिक महत्वपूर्ण तथ्य और प्रमाण होते हैं। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए।

लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को मिलने की अनुमति क्यों?

लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है, राजतंत्र में सत्ता राजा की होती है जबकि लोकतंत्र में सत्ता जनता की होती है। राजा तक पहुंचने के लिए अनुमति आवश्यक हो सकती थी, लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि किसी अधिकारी, प्रशासनिक प्रमुख अथवा संवैधानिक संस्था के प्रमुख से जनता की समस्या रखने के लिए अनुमति मिलने तक दरवाजे पर खड़ा रहे, मिलने के लिए अनुमति मागे, यह स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़ा करती है। जनप्रतिनिधि जनता के मत से निर्वाचित होकर संसद या विधानसभा या नगरी निकायों तक पहुंचता है। उसका दायित्व केवल सदन में बैठना नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार, प्रशासन तथा संवैधानिक संस्थाओं तक पहुंचाना भी है। इसलिए निर्यातित प्रतिनिधि, शासन-प्रशासन के बीच संवाद लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है। सामान्य लोकतांत्रिक परंपरा यही रही है, सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी अथवा संवैधानिक पदाधिकारी से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं, यदि संभवित अधिकारी उनसे समग्र उपलब्ध नहीं होता है, तो सुविधा के अनुसार सम्मानपूर्वक जनप्रतिनिधि से समय तय करता है। जनप्रतिनिधि को मिलने से पहले अनुमति लेना या मिल सकता है, या नहीं,

यह व्यवस्था लोकतांत्रिक संवाद को नौकरशाही की अनुमति पर निर्भर बना सकती है। ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधि का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हाल ही में लगभग 300 सांसदों द्वारा चुनाव आयोग से मिलने की कोशिश के प्रयास ने इसी प्रश्न को जन्म दिया है। यदि इतने सांसद एक साथ किसी संवैधानिक संस्था तक पहुंच रहे थे, पूर्व सूचना होने के बाद भी उनके बैठने की प्र्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, चुनाव आयोग के कार्यालय में प्रतिनिधि मंडल से मिलना संभव नहीं था, ऐसी स्थिति में क्या भारत से ज्ञापन नहीं लिया जा सकता था? क्या आयोग का कोई अधिकारी उनसे मिलकर उनकी बात नहीं सुन सकता था? लोकतंत्र में असहमति और मजबूती और लोकतांत्रिक व्यवस्था का जीता-जागता प्रमाण है।

इससे भी बड़ा प्रश्न यह है, सांसदों को संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय तक जाने से पुलिस रोकती है। तो ऐसी कार्रवाई किसके आदेश पर हुई? दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई क्यों की? जनप्रतिनिधियों को जाने से रोकना, किस अधिकार के तहत किया गया? किस लोकतांत्रिक आवश्यकता या किस कानून के तहत रोका गया? जनप्रतिनिधियों को रोकने के लिए कानून और व्यवस्था का

तर्क दिया जा सकता है, लेकिन यह शांतिपूर्ण पैदल मार्च था। जितनी कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की थी वहीं जिम्मेदारी इन सांसदों की भी थी। फिर भी उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया गया। स्पष्ट रूप से यह कृत्य सांसदों के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने जैसा है। समस्या केवल एक घटना या किसी एक संस्था की नहीं है। संसद और विधानसभाओं में जन प्रतिनिधियों को बोलने के लिए समय, नियम और प्रक्रियाओं की दीवारों से गुजरना पड़ता है। बोलने के पहले ही उनसे ऑथेंटिकेशन मांगा जाता है। नियम आवश्यक हैं, क्योंकि संसद अनुशासन से चलता है। नियमों का उद्देश्य जन प्रतिनिधियों की आवाज को दबाना नहीं, बल्कि हर पक्ष को अपनी बात रखने का अवसर देना होना चाहिए। जनता का चुनाव हुआ प्रतिनिधि अपनी बात अपने ही सदन में नहीं रख पाएगा, तो फिर लोकतंत्र में जनता की आवाज कहां सुनी जाएगी?

इसी प्रकार प्रशासनिक और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही लोकतंत्र का मूल तत्व है। साफ़ या विधायक किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि जनता की समस्या को लेकर अधिकारी के पास जाता है। यदि उसे लगातार जवाब न मिले, मुलाकात न हो, ज्ञापन स्वीकार न

किया जाए और समस्याएं लंबित रहें, तो धीरे-धीरे जनता का विश्वास शासन-प्रशासन और संवैधानिक संस्थाओं से उठने लगता है। लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं है।लोकतंत्र का अर्थ है, जनता की सत्ता, शासन एवं प्रशासन में भागीदारी, निर्वाचित प्रतिनिधियों की गरिमा, संस्थाओं की स्वतंत्रता, प्रशासन की जवाबदेही और सभी पक्षों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता उसका मौलिक अधिकार है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जनप्रतिनिधि का सम्मान व्यक्ति का नहीं बल्कि उस जनता का सम्मान है, जिस मतदाताओं के समूह टकराव बढ़ रहा है। लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बंट रहा है। वह लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है। संस्थाएं जब संवाद के दरवाजे बंद करती हैं, तो असंतोष सड़क पर आता है। जब संवैधानिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास कमजोर होता या टूटता है, ऐसी स्थिति में भीड़तंत्र मजबूत होने लगता है। भीड़ स्वयं न्याय करने के लिए सड़क पर निकल पड़ती है। भीड़ के पास संस्था और शक्ति हो सकती है, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। लोकतंत्र को बनाए रखने की पहली शर्त है, जन प्रतिनिधियों को बोलने दिया जाए, उनकी बात सुनी जाए।

जन प्रतिनिधियों द्वारा जो मुद्दे उठाए जाते हैं। उन समस्याओं का समय पर समाधान हो, जन प्रतिनिधि और आम जनता को विश्वास में लिया जाए। जन प्रतिनिधियों का भी कर्तव्य है, वह संवैधानिक मर्यादों, नियम और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करें। अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ चलेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। भारत ने कई दशकों की लोकतांत्रिक यात्रा में अनेक कठिन परिस्थितियों के बावजूद संस्थाओं को मजबूत किया है। वर्तमान चुनौती यह है, संवाद के दरवाजे जो बंद होते जा रहे हैं, इनको खुला रखा जाए। लोकतंत्र में सत्ता का प्रमाण यह नहीं है, सरकार कितनी शक्तिशाली है। मजबूत सरकार की पहचान इस बात से होती है, वह असहमति की आवाज कितनी सहजता से सुन सकती है। जन प्रतिनिधि जनता की आवाज है। उस आवाज को सुनने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती है। उस आवाज को सुनने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में मौलिक है। वही जन प्रतिनिधियों को चुनती है। वही जनता के लिए कानून बनाते हैं। कानून के आधार पर समानता के साथ सभी को मौलिक अधिकारों के साथ रहने का अवसर मिलता है। यदि इसमें कमी आएगी, ऐसी स्थिति में लोकशाही को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। इस बात को सभी को समझना होगा।

लेखक- सनत जैन

नमः स्फुशं दीपतम अर्थात् गौरव के साथ आकाश को छूना। भारतीय वायुसेना का यह ध्येय वाक्य केवल शब्द नहीं, बल्कि उस अदम्य संकल्प का प्रतीक है जिसमें साहस, शौर्य, तकनीकी दक्षता और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति सर्वोच्च समर्पण निहित है। इसकी प्रेरणा श्रीमद्भगवद्गीता के 11वें अध्याय के उस प्रसंग से जुड़ी है जिसमें भगवान श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए उनके तेजोमय स्वरूप के आकाश को स्पर्श करने का उल्लेख मिलता है।

यही भाव भारतीय वायुयुद्धाओं के साहस और कर्तव्यनिष्ठा में दिखाई देता है, जो हर परिस्थिति में देश के आकाश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को अस्तित्व में आई भारतीय वायुसेना वर्ष 2026 में अपनी 94वीं वर्षगांठ मना रही है। छह अर्धशताब्दी में 19 एयरमैन से शुरू हुई इसकी यात्रा आज आधुनिक लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, परिवहन विमानों, रडार, मिसाइलों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों और नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता से लैस एक महत्वपूर्ण सामरिक शक्ति में बदल चुकी है। आज भारतीय वायुसेना में 1.40 लाख से अधिक सक्रिय सैन्यकर्म हैं। वायुसेना दिवस आत्ममंथन का भी दिन है कि बदलते युद्ध के दौर में हमारी वायुशक्ति कितनी तैयार है और आने वाली चुनौतियों के लिए हमें क्या करना होगा। भारतीय वायुसेना की उपलब्धियों का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है।

1947-48, 1965 और 1971 के युद्धों से लेकर कारगिल संघर्ष तक वायुसेना ने अपनी भूमिका साबित की है। समय के साथ युद्ध का स्वरूप बदला है और अब केवल पायलट की वीरता या विमान की गति निर्णायक नहीं होती। आधुनिक युद्ध

में रडार, उपग्रह, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, लंबी दूरी की मिसाइलें, सुरक्षित संचार और रियल टाइम सूचना भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई हैं। इसलिए आज वायुशक्ति का अर्थ केवल लड़ाकू विमानों की संख्या नहीं, बल्कि एक संपूर्ण और परस्पर जुड़ी हुई युद्ध प्रणाली है। इसीलिए भविष्य की भारतीय वायुशक्ति में लड़ाकू विमानों के साथ एयरबोर्न अल्टी वॉर्निंग सिस्टम, हवा में ईंधन भरने वाले विमान, ड्रोन, मिसाइल और मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क की भूमिका बढ़ने वाली है। इसी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की दीर्घकालिक मजबूती के लिए अनिवीर वायुसैनिकों के स्थान पर पर्याप्त नियमित वायुसैनिकों की भर्ती अपरिहार्य है। भारतीय वायुसेना की वास्तविक चुनौती यही से शुरू होती है। स्वीकृत 42 लड़ाकू स्वाइनों के मुकाबले सक्रिय स्वाइनों की उपलब्धता का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है।

सामने आती रही हैं और 2026 में यह संख्या लगभग 29 तक बताई गई है। यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरी ओर पुराने मिग-21 के विदा होने के साथ जगुआर, मिगान-2000 और मिग-29 जैसे अपेक्षाकृत पुराने बड़े के आधुनिकीकरण

अथवा भविष्य में चरणबद्ध सेवानिवृत्ति की चुनौती भी सामने है। समस्या केवल विमानों की कमी की नहीं है, बल्कि पुराने विमानों के हटने और नए विमानों के शामिल होने के बीच पैदा होने वाले अंतर की है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी इस चुनौती को कई बार रेखांकित कर चुके हैं। फरवरी 2025 में उन्होंने कहा था कि देश को हर वर्ष लगभग 35 से 40 लड़ाकू विमानों का उत्पादन करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी उत्पादन क्षमता तारोंतर तैयार नहीं हो सकती। यह टिप्पणी बताती है कि भारत के सामने चुनौती केवल विमान खरीदने की नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थायी औद्योगिक क्षमता तैयार करने की है जो संकट के समय लगातार विमानों और उनके कलपुर्जों की आपूर्ति कर सके। इस दिशा में तेजस कार्यक्रम उम्मीद की महत्वपूर्ण किरण है।

सितंबर 2025 में रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ 97 तेजस एम्फे-1ए विमानों के लिए 62370 करोड़ रुपये से अधिक का अनुबंध किया। इनमें 68 लड़ाकू विमान और 29 टिवन-सौटर शामिल हैं। इनकी आपूर्ति 2027-28 से शुरू

होकर छह वर्षों में पूरी होनी है। इन विमानों में 64 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री रखने तथा उत्तम एईएसए रडार और अन्य स्वदेशी प्रणालियों को शामिल करने की योजना है। सितंबर 2026 में एचएएल द्वारा तेजस एफओसी टिवन-सीटर शक्तिश्रक विमानों की वायुसेना को सुपुर्दगी भी स्वदेशी एयरोस्पेस क्षमता के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही है। लेकिन केवल तेजस पर निर्भर रहकर तत्काल कमी पूरी नहीं की जा सकती। इसी कारण 114 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों की संभावित बड़ी डील पर बातचीत जारी रहने की पुष्टि की है, जिसमें भारत में विमानों के निर्माण की संभावना भी शामिल है। भारतीय वायुसेना के सामने चुनौतियां गंभीर अवश्य हैं, लेकिन सापथ्य की कमी नहीं है। हमारे पास अनुभवी और साहसी वायुयुद्धा, राफेल और सुखोई-30 एम्फेआई जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान, तेजस जैसी स्वदेशी पहल, मजबूत मिसाइल क्षमता और तेजी से विकसित होता रक्षा उद्योग है। जरूरत इस बात की है कि

आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में गति, उत्पादन में निरंतरता और स्वदेशी तकनीक में निवेश को समान प्राथमिकता मिले। ह्रदयमः स्फुशं दीप्तमह्म का वास्तविक अर्थ तभी सार्थक होगा जब भारत अपने आकाश को केवल साहस के भरपore नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक, पर्याप्त संख्या में लड़ाकू विमानों, मजबूत वायु रक्षा, विश्वसनीय हथियार प्रणालियों, प्रशिक्षित मानव संसाधन और आत्मनिर्भर औद्योगिक क्षमता से सुरक्षित रखे। आकाश को छूना गौरव को बात है, लेकिन उस विशाल आकाश की सुरक्षा के लिए हर समय तैयार रहना उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी है।

भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस पर देश के वीर वायुयुद्धाओं को नमन करते हुए यही संकल्प होना चाहिए कि बदलती युद्ध तकनीक के नई सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत की वायुशक्ति न केवल सक्षम रहे, बल्कि भविष्य की जरूरतों के अनुरूप निरंतर मजबूत होती रहे। वायुसेना दिवस पर शराश्र सेनाओं के अधिकारियों/सैनिकों को हार्दिक बधाइयां, जयहिंद! आओ, वायु सेना की मजबूती का संकल्प लें।

अनुज आचार्य, लेखक बैजनाथ से हैं

आलेख

देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने वाली संस्थाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर उठते सवाल चिंता का विषय हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार गंभीर आरोप लगा रहा है। विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया के तहत 13 करोड़ से अधिक नाम मतदाता सूची से बाहर हो चुके हैं। यदि यह आंकड़ा सही है, तो यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा प्रश्न है। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और उसमें मौजूद गलतियों को दूर करना बताया जाता है। लेकिन किसी भी पुनरीक्षण प्रक्रिया की विश्वसनीयता तभी कायम रह सकती है, जब उसके नियम, आंकड़े और निर्णय सार्वजनिक हों। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसलिए उसके हर बड़े फैसले की जानकारी राजनीतिक दलों, नागरिक संगठनों, मीडिया और आम जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखी जानी चाहिए। पारदर्शिता से बचने की कोई भी कोशिश सदेह को जन्म देती है।

विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग एसआईआर से जुड़े सवालों का खुलकर जवाब नहीं दे रहा है। सबसे अधिक विवाद ऑनलाइन फॉर्म-6 में किए गए बदलाव को लेकर है। फॉर्म-6 का इस्तेमाल नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए किया जाता है। एसआईआर के दौरान इस फॉर्म में एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र जोड़े जाने की बात सामने आई। इसके तहत नए स्वयं या उसके माता-पिता पिछली एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में मैप किया गए थे या नहीं। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और उन परिवारों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाती है, जिनके पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में गरीब, ग्रामीण, प्रवासी और वंचित समुदायों के लोगों को अपने नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में कठिनाई हो सकती है। यदि किसी नागरिक से ऐसे दस्तावेज या घोषणाएं मांगी जाती हैं, जिनकी व्यवस्था उसके लिए आसान

नहीं है, तो वह मताधिकार से वंचित हो सकता है।

फॉर्म-6 में हुए इस बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई ने विवाद को और गंभीर बना दिया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सुर्वकांत ने कथित तौर पर कहा कि अदालत ने किसी संशोधित फॉर्म-6 को मंजूरी नहीं दी है। इसके विपरीत चुनाव आयोग की ओर से यह दावा किया जाता रहा कि फॉर्म में बदलाव सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद किया गया। यदि अदालत की टिप्पणी और चुनाव आयोग के दावे में अंतर है, तो इसकी स्पष्ट व्याख्या आवश्यक है। यह केवल शब्दों का विवाद नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा मामला है। रिपोर्टों के अनुसार, चुनाव आयुक्तों सुखबोर्ड सिंह संघू अश्व और विवेक जोगी ने भी इस बदलाव पर आपत्ति जताई थी। यदि आयोग के भीतर ही किसी निर्णय को लेकर मतभेद मौजूद थे, तो उस पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे जनता को यह समझने में मदद मिलेगी कि निर्णय किस आधार पर लिया गया और उसमें किन अधिकारियों की क्या भूमिका

थी। संवैधानिक संस्थाओं में आंतरिक असहमति लोकतंत्र के लिए असामान्य नहीं है, लेकिन उसे छिपाने से संस्थागत भरोसा कमजोर होता है। इन्हें सवालों के चलते विपक्ष एसआईआर को रद्द करने की मांग कर रहा है। मंगलवार को इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद परिसर से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की कोशिश की। उनका उद्देश्य चुनाव आयुक्तों से मुलाकात कर अपनी आपत्तियां दर्ज कराना था। सांसदों के हाथों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस्तीफे की मांग वाले पोस्टर भी थे।

मार्च शुरू होते ही दिल्ली पुलिस ने सांसदों को रोक दिया और कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। अखिलेश यादव, डेरेक ओल्डब्रानन और अभिषेक बनर्जी सहित अनेक सांसदों को बसों में बैठाया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा भी अन्य सांसदों के साथ आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंच गए, जो चुनाव आयोग के कार्यालय से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। विपक्षी सांसदों ने वहीं धरना शुरू कर दिया और चुनाव आयोग के दूसरे प्रवेश द्वार से अधिकारियों से मिलने की

कोशिश की, लेकिन उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में कहा कि 300 से अधिक विपक्षी सांसद संसद से चुनाव आयोग तक पदयात्रा करके आए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ये सांसद करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो चुनाव आयुक्त उनसे मिलने से क्यों बच रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने जा रहे जनप्रतिनिधियों को क्यों रोक रही है। यह सवाल पूरी तरह जायज है। चुनाव

आयोग किसी राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं, बल्कि देश की संवैधानिक चुनावी संस्था है। राजनीतिक दलों को अपनी आपत्तियां और शिकायतें सीधे चुनाव आयोग के सामने रखने का अधिकार है। आयोग किसी प्रतिनिधिमंडल से मिलना चाहता है या नहीं, यह प्रशासनिक निर्णय हो सकता है, लेकिन निर्वाचित सांसदों के साथ संवाद से पूरी तरह बचना लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप नहीं कहा जा सकता।

विपक्षी नेताओं ने पुलिस कार्रवाई पर

भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के कामकाज पर आपत्तियां पहली बार नहीं उठ रही हैं। उनके अनुसार, कई मौकों पर ऐसा लगता है कि आयोग सभी राजनीतिक दलों को समान दृष्टि से नहीं देख रहा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया। उनका सवाल था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी।

लोकतंत्र में असहमति को दबाने के बजाय सुना जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के बीच मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन चुनावी प्रक्रिया पर उठने वाले सवालों का उत्तर तथ्यों, दस्तावेजों और सार्वजनिक संवाद के माध्यम से दिया जाना चाहिए। यदि एसआईआर में किसी नागरिक का नाम हटया गया है, तो उसके लिए अपील और सुधार की सरल व्यवस्था होनी चाहिए। चुनाव आयोग को यह भी बताना चाहिए कि कितने नाम हटाए गए,

किन कारणों से हटाए गए और प्रभावित नागरिकों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का कितना अवसर दिया गया। सरकार और चुनाव आयोग दोनों की जिम्मेदारी है कि वे लोकतंत्र में जनता का विश्वास बनाए रखें। विपक्ष के आरोप सही हैं या नहीं, इसका निर्णय तथ्यों और स्वतंत्र जांच से होना चाहिए। लेकिन अवसर पूछने वालों को रोकना, मिलने का अवसर न देना और पारदर्शी जानकारी उपलब्ध न कराना संदेह को और गहरा करता है।

लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं है। यह नागरिकों के मताधिकार, संस्थाओं की निष्पक्षता, राजनीतिक असहमति के सम्मान और सार्वजनिक जवाबदेही पर आधारित व्यवस्था है। इसलिए एसआईआर से जुड़े सभी आंकड़े, नियम और निर्णय सार्वजनिक किए जाने चाहिए। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के साथ खुला संवाद करना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा केवल सत्ता पक्ष या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर संवैधानिक संस्था और नागरिक की साझा जिम्मेदारी है।

लेखक - सचिन कुमार गौतम



संक्षिप्तवार्ता

बस में नाबालिग से गैंगरेप: ड्राइवर-कंडक्टर पर आरोप तय

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर (वेब वार्ता)। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आ रही चलती स्लीपर बस में नाबालिग छात्रा को के साथ कथित सामूहिक दुरकर्म के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने बस चालक और कंडक्टर के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। फास्ट ट्रैक अदालत में दोनों आरोपियों के खिलाफ नाबालिग के अपहरण, गलत तरीके से रोकने, सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर से शुरू होगी।

यह मामला 4 अगस्त 2026 का है। पुलिस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली नाबालिग छात्रा नोएडा के सेक्टर–63 में अपने रिश्तेदार से मिलने जा रही थी। रास्ते में वह पूरी चौक के पास उतर गई थी। इसी दौरान उसने एक स्लीपर बस को रूकवाकर चालक और कंडक्टर से नोएडा जाने के बारे में जानकारी ली। आरोप है कि उसे बताया गया कि बस सेक्टर –63 की ओर जा रही है, जिसके बाद वह बस में सवार हो गई।

दिल्ली के करावल नगर में चाकू से गोदकर भतीजे की हत्या

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर (वेब वार्ता)। पूर्वी दिल्ली के करावल नगर थाना क्षेत्र में रिश्तो को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। बुधवार रात किसी बात को लेकर हुए विवाद में एक चाचा ने अपने 35 व्षीय भतीजे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। भाई को बचाने पहुंचे छोटे भाई पर भी जानलेवा हमला किया गया। वहीं, गंभीर रूप से घायल भतीजे को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान हिमांशु भारद्वाज उर्फ जीत शर्मा के रूप में हुई है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा व अन्य ने दी खंडेलवाल को जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार के मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष ने चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल को जन्मदिन की बधाई दी है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक्स पोस्ट पर प्रभु श्रीराम से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए कहा कि राष्ट्रहित, दिल्ली के विकास और जनकल्याण के प्रति उनका सेवाभाव निरंतर इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता रहे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी प्रवीण खंडेलवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और सुदृढ़ जीवन की कामना की। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सांसद को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके सरल स्वभाव, कर्मठता और जनसेवा के प्रति समर्पण की सराहना की। उन्होंने वाहेगुरु जी से प्रवीण खंडेलवाल के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुख–समृद्धि की अरदास की तथा निरंतर जनसेवा करते रहने की कामना की। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, शिक्षा मंत्री आशीष सुद और स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने भी चांदनी चौक सांसद को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

हजारों कॉकरोच पकड़ लिए जाने का दावा; आशुतोष रांका ने कहा- 2.5 करोड़ हैं हम

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर (वेब वार्ता)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने आरोप लगाया है कि 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर–मंतर पर होने जा रहे विरोध प्रदर्शन से पहले उसके हजारों वॉलेंटियर्स को हिरासत में लिया जा रहा है। सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने दावा किया गया कि महाराष्ट्र, यूपी और पश्चिम बंगाल जैसी राज्यों में पुलिस ऐसा कर रही है। उन्होंने इसके साथ ही यह भी कहा कि कितनों को अरेस्ट किया जाएगा, 2.5 करोड़ कॉकरोच हैं।

मुख्यमंत्री ने सेंट्रल पार्क में प्लांट मंडल रंगोली का किया शुभारंभ

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कर्नाट प्लेस के सेंट्रल पार्क में दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष महतोत्रा के साथ प्लांट मंडला रंगोली का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जीवित पौधों से सजी यह सुंदर मंडला रंगोली हमारी भारतीय कला परंपरा और प्रकृति के प्रति प्रेम का अनूठा उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ हम अपनी दिल्ली को भी हरित, सुंदर और विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप भी अपने परिवार के साथ सेंट्रल पार्क जरुर आएं और इस सुंदर प्लांट मंडला आर्ट का आनंद लीजिए। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, दिल्ली भाजपा प्रदेश महामंत्री योगिता सिंह एवं विधायक अशोक गोयल उपस्थित रहे।

डीडीए का फैसला; दिल्ली के 45 झुग्गी क्लस्टरस का होगा पुर्नवास, मिलेंगे पक्के मकान

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर (वेब वार्ता)। डीडीए ने दिल्ली के 45 झुग्गी-झोपड़ी यानी जेजे क्लस्टरों का उसी स्थान पर पुनर्वास करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे इन क्लस्टरों में रहने वाले लगभग 21,229 परिवारों को उसी जगह पक्के मकान मिलेंगे। इन परिवारों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस कदम से एक लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। साथ ही अतिरिक्त आवास और व्यावसायिक विकास के लिए भूमि उपलब्ध हो सकती है।

21,229 परिवारों का होगा पुनर्वास
अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने 45 झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टरों में रहने वाले लगभग 21,229 परिवारों के मौजूदा स्थान पर ही पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम से एक लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने का अनुमान है। डीडीए की ओर से अतिरिक्त आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है।

15 परियोजनाओं पर शुरू होगा

छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस में अंधेरी जगहें, लाइटिंग की कमी, टूटे फूटपाथ और कचरे की समस्या के जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार देर रात दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस का दौरा किया और आर्ट्स फैकल्टी के बाहर छात्राओं से मिलकर उनकी चिंताओं को सीधे सुना। यह जानकारी उन्होंने मुख्यमंत्री ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई समस्याएं सामने आईं, जैसे अंधेरी जगहें, स्ट्रीट लाइटिंग की कमी, टूटे–फूटे फुटपाथ, सीसीटीवी कवरेज में कमी और कचरा जमा होना। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे विना किसी देरी के हर समस्या का समाधान करें और इस पर अमल की बारीकी से निगरानी की जाएगी।

मलबे के नीचे से गर्भवती महिला ने पानी के लिए परिजनों को किया फोन किया, अस्पताल में मौत

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में इमारत ढहने पर मलबे में कई घंटे तक फंसी रही चार महीने की गर्भवती गुलफसा ने फोन कर पानी देने की गुहार लगाई और बचावकर्मियों को अपनी जगह की जानकारी दी, जिसके बाद उसे निकाल कर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि वह अपने माता-पिता के घर पर थीं, तभी अपार्टमेंट की इमारत अचानक ढह गई और वह मलबे में दब गई। उन्होंने बताया कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बुधवार दोपहर चार मंजिला एक इमारत ढह गई, जिसमें गुलफसा और डेढ़ साल के एक बच्चे समेत कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई तथा आठ लोग घायल हुए हैं। गुलफसा (21) के रिश्तेदारों ने बताया कि घर में गुड़िया नाम से पुकारे जाने वाली गुलफसा इमारत की दूसरी मंजिल पर नहा रही थी, तभी इमारत ढह गई और वह मलबे में दब गई।

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में 59 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर की गोली लगने से मौत

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जसोला इलाके में बुधवार को एक गोलीम में 59 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि एहतेशाम उद्दीन आजमी सरिता विहार स्थित एक प्लॉट में घायल अवस्था में मिले। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से एक देसी पिस्तौल, दो कारतूस और एक खोख़ा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक, मृतक के परिवार ने अभी तक किसी से दुश्मनी होने या घटना में किसी अन्य व्यक्ति के शामिल होने की बात नहीं कही है। पुलिस ने कहा कि अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है और यह जांच की जा रही है कि गोली किन परिस्थितियों में चली।

फरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

दिल्ली पुलिस सीजेपी के जुलाई प्रदर्शन में पूर्व नियोजित हिंसा और आपराधिक तत्वों की भूमिका की करेगी जांच

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दिल्ली पुलिस की काइम ब्रांच ने जुलाई में राजधानी में कॉकरेच जनता पार्टी (सीजेपी) के पददर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया कि जांच का मुख्य फोकस 20 जुलाई को नई दिल्ली में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका पर रहेगा। जांच में विशेष रूप से

दिल्ली



काम

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डीडीए ने राष्ट्रीय राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में 135.74 एकड़ में फैले 45 झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टरों से जुड़े 15 परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए तीन लेन-देन सलाहकारों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव आमंत्रण जारी किया गया है।

नए इलाके बनाने का रास्ता साफ

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के

मंत्रालय ने अगस्त में दिल्ली की महायोजना

2047 को अधिसूचित किया। इस योजना

से दिल्ली में ऊंची इमारतें और घनी आबादी

वाले नए इलाके विकसित करने का रास्ता

साफ हो गया है। इसके साथ ही 650 से

अधिक झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में रहने

वाले लगभग 17 लाख लोगों को उसी स्थान

पर पुनर्वास कराया जाएगा।

लेन-देन सलाहकार का चयन आर्थिक

मामलों के विभाग या राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण

निगम के साथ सूचीबद्ध कंपनियों में से

किया जाएगा। ये सलाहकार चुने गए

क्लस्टरों की पुनर्वास संबंधी जरूरतों,

विकास की संभावनाओं और आधारभूत

ढांचे की जरूरतों का आकलन करेंगे।

जांची जाएगी आर्थिक व्यवहार्यता

डीडीए के अधिकारियों के अनुसार,

परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता की

जांच की जाएगी और उन्हें लागू करने के

लिए उपयुक्त मॉडल सुझाए जाएंगे। उम्मीद

है कि व्यवहार्यता रिपोर्ट से परियोजनाओं

को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए

तकनीकी और वित्तीय रूपरेखा तैयार

होगी।

क्या है उसी स्थान पर पुनर्वास

मंडल?

इस पुनर्वास मॉडल में उसी स्थान पर

नए मकान बनाए जाते हैं, ताकि निवासियों

को दूर नहीं जाना पड़े और उन्हें बेहतर

आवास मिल सके। डीडीए के अनुसार, इस

परियोजना से अतिरिक्त आवास और

व्यावसायिक स्थान भी तैयार होंगे। इससे

बड़ी आबादी को आवासीय और

व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने में मदद

मिलेगी।

राहुल गांधी के प्रदर्शन के बीच कर्नाट प्लेस में दोगुनी पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स की 300 कंपनी तैनात, सभी रास्ते बंद

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर (वेब वार्ता)। राजधानी में बीते तीन दिनों से मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन का गुरुवार को चौथा दिन है। इस दौरान कर्नाट प्लेस का नजारा बदल गया है। चप्पे-चप्पे पर दिल्ली समेत बाहरी राज्यों से बुलाई गई पुलिस तैनात है और 300 अर्द्ध सैनिक बलों की 300 कंपनियों की तैनाती गई है। ड्रोने से भी निगरानी रखी जा रही है। बाहरी राज्यों से भी पुलिस बुलाने के साथ ही दिल्ली के सभी आउटर जिले में चार–चार अस्थाई डिंटेशन सेंटर बना दिए गए हैं, जहां प्रदर्शनकारियों को रखने का इंतजाम किया गया है। शाम तक यहां का नजारा

कफ्यू जैसा भी हो सकता है। एक ओर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़ी संख्या युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कर्नाट प्लेस में उमड़े हैं तो दिल्ली पुलिस हर रास्ते पर घेराबंदी

कर दी है। टॉलस्टॉय मार्ग, जनपथ,

संसद मार्ग आदि सभी सड़कों पर वज्र

वाहन खड़े कर दिए गए हैं। वहीं, दिल्ली

के सभी आउटर जिले में चार–चार

अस्थाई डिंटेशन सेंटर बना दिए गए हैं,

कौ जाए।

यह कार्रवाई 24 वर्षीय युवक की गिरफ्तारी

की सूष्ट्रभूमि में हुई है। उस व्यक्ति पर कुत्रिम

मेधा (एआई) से बनाया गया वीडियो प्रसारित

करने का आरोप है, जिसमें गलत तरीके से

एक पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर एक

महिला का यौन उत्पीड़न करते दिखाया गया

था। पुलिस ने कहा कि वह इस बात की जांच

कर रही है कि क्या इस फर्जी सामग्री का प्रसार

दिल्ली पुलिस को बदनाम करने और प्रदर्शनों

के दौरान असंतोष पैदा करने की किसी बड़ी

साजिश का हिस्सा था।

नोटिस के अनुसार इन 11 पोस्ट में ऐसे

वीडियो थे जो उस प्रदर्शन से संबंधित थे।

प्रदर्शन के दौरान कानून–व्यवस्था बनाए रखने

और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए

कौ जाए।

यह कार्रवाई 24 वर्षीय युवक की गिरफ्तारी

की सूष्ट्रभूमि में हुई है। उस व्यक्ति पर कुत्रिम

मेधा (एआई) से बनाया गया वीडियो प्रसारित

करने का आरोप है, जिसमें गलत तरीके से

एक पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर एक

महिला का यौन उत्पीड़न करते दिखाया गया

था। पुलिस ने कहा कि वह इस बात की जांच

कर रही है कि क्या इस फर्जी सामग्री का प्रसार

दिल्ली पुलिस को बदनाम करने और प्रदर्शनों

के दौरान असंतोष पैदा करने की किसी बड़ी

साजिश का हिस्सा था।

नोटिस के अनुसार इन 11 पोस्ट में ऐसे

वीडियो थे जो उस प्रदर्शन से संबंधित थे।

प्रदर्शन के दौरान कानून–व्यवस्था बनाए रखने

और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए

कौ जाए।

यह कार्रवाई 24 वर्षीय युवक की गिरफ्तारी

की सूष्ट्रभूमि में हुई है। उस व्यक्ति पर कुत्रिम

मेधा (एआई) से बनाया गया वीडियो प्रसारित

करने का आरोप है, जिसमें गलत तरीके से

एक पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर एक

महिला का यौन उत्पीड़न करते दिखाया गया

था। पुलिस ने कहा कि वह इस बात की जांच

कर रही है कि क्या इस फर्जी सामग्री का प्रसार

दिल्ली पुलिस को बदनाम करने और प्रदर्शनों

के दौरान असंतोष पैदा करने की किसी बड़ी

साजिश का हिस्सा था।

नोटिस के अनुसार इन 11 पोस्ट में ऐसे

वीडियो थे जो उस प्रदर्शन से संबंधित थे।

प्रदर्शन के दौरान कानून–व्यवस्था बनाए रखने

और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए

कौ जाए।

यह कार्रवाई 24 वर्षीय युवक की गिरफ्तारी

की सूष्ट्रभूमि में हुई है। उस व्यक्ति पर कुत्रिम

मेधा (एआई) से बनाया गया वीडियो प्रसारित

करने का आरोप है, जिसमें गलत तरीके से

एक पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर एक

महिला का यौन उत्पीड़न करते दिखाया गया

था। पुलिस ने कहा कि वह इस बात की जांच

कर रही है कि क्या इस फर्जी सामग्री का प्रसार

दिल्ली पुलिस को बदनाम करने और प्रदर्शनों

के दौरान असंतोष पैदा करने की किसी बड़ी

साजिश का हिस्सा था।

नोटिस के अनुसार इन 11 पोस्ट में ऐसे

वीडियो थे जो उस प्रदर्शन से संबंधित थे।

प्रदर्शन के दौरान कानून–व्यवस्था बनाए रखने

और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए

कौ जाए।

यह कार्रवाई 24 वर्षीय युवक की गिरफ्तारी

की सूष्ट्रभूमि में हुई है। उस व्यक्ति पर कुत्रिम

मेधा (एआई) से बनाया गया वीडियो प्रसारित

करने का आरोप है, जिसमें गलत तरीके से

एक पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर एक

महिला का यौन उत्पीड़न करते दिखाया गया

था। पुलिस ने कहा कि वह इस बात की जांच

कर रही है कि क्या इस फर्जी सामग्री का प्रसार

दिल्ली पुलिस को बदनाम करने और प्रदर्शनों

के दौरान असंतोष पैदा करने की किसी बड़ी

साजिश का हिस्सा था।

नोटिस के अनुसार इन 11 पोस्ट में ऐसे

वीडियो थे जो उस प्रदर्शन से संबंधित थे।

प्रदर्शन के दौरान कानून–व्यवस्था बनाए रखने

और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए

कौ जाए।

यह कार्रवाई 24 वर्षीय युवक की गिरफ्तारी

की सूष्ट्रभूमि में हुई है। उस व्यक्ति पर कुत्रिम

मेधा (एआई) से बनाया गया वीडियो प्रसारित

करने का आरोप है, जिसमें गलत तरीके से

एक पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर एक

महिला का यौन उत्पीड़न करते दिखाया गया

था। पुलिस ने कहा कि वह इस बात की जांच

कर रही है कि क्या इस फर्जी सामग्री का प्रसार

दिल्ली पुलिस को बदनाम करने और प्रदर्शनों

के दौरान असंतोष पैदा करने की किसी बड़ी

साजिश का हिस्सा था।

नोटिस के अनुसार इन 11 पोस्ट में ऐसे

वीडियो थे जो उस प्रदर्शन से संबंधित थे।

प्रदर्शन के दौरान कानून–व्यवस्था बनाए रखने

और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए

कौ जाए।

यह कार्रवाई 24 वर्षीय युवक की गिरफ्तारी

की सूष्ट्रभूमि में हुई है। उस व्यक्ति पर कुत्रिम

मेधा (एआई) से बनाया गया वीडियो प्रसारित

करने का आरोप है, जिसमें गलत तरीके से

एक पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर एक

महिला का यौन उत्पी

संक्षिप्तवार्ता

ऑरचिड चौराहे का नाम रामविलास पासवान चौराहा रखने की मांग

मुरादाबाद (वेब वार्ता)

लोक जनशक्ति पार्टी की मुरादाबाद युवा इकाई ने पार्टी के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की स्मृति में महानगर मुरादाबाद के ग्रीन ऑरचिड चौराहे का नाम रामविलास पासवान चौराहा किए जाने की मांग उठाई है। संगठन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिलाधिकारी को पेश किए गए ज्ञापन में नया मुरादाबाद में रामविलास पासवान की स्मृति में पार्क बनाने की मांग भी उठाई गई है। प्रतिनिधि मंडल में जिला अध्यक्ष कपिल कुमार शर्मा के अलावा सुमित रस्तोगी गुलजार खान गौरी शंकर अनुज शर्मा एवं विवेक आदि मौजूद रहे.

15 हजार रुपये की रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार, नोट जलाने का भी आरोप

वेब वार्ता, ललितपुर

भ्रष्टाचार निवारण संगठन की झांसी इकाई ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए राजस्व लेखपाल विपुल तिवारी को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि ग्राम टौरिया की जमीन पर कब्जा बरकरार रखने और धारा 30(2) की कार्रवाई में पक्ष में राय देने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत के अनुसार पहले 20 हजार रुपये की मांग की गई, बाद में 15 हजार रुपये में सौदा तय होने का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद टीम ने ट्रैप कार्रवाई की। संगठन के मुताबिक टीम के पहुंचने पर लेखपाल ने दरवाजा बंद कर रिश्वत के नोट जलाने का प्रयास किया। मौके से जले हुए नोटों के अवशेष बरामद होने और हाथों के रासायनिक परीक्षण में पानी का रंग गुलाबी होने की बात कही गई है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

मेडिकल स्टोर की सलाह पर न लगाएं दाद-खाज की क्रीम

वेब वार्ता, कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सर्जम (डमेटीलॉजी) विभाग द्वारा फंगल इंफेक्शन के मरीजों पर किए गए एक विशेष सर्वे में गंभीर और चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 6 सप्ताह से अधिक पुराने इंफेक्शन से पीड़ित 200 मरीजों पर किए गए इस अध्ययन में पाया गया कि इनमें से 114 मरीज बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के स्टैचोयड युक्त क्रीमों का इस्तेमाल कर रहे थे। सर्वे के अनुसार, मरीज लोबेट जीएम, सल्फाज एसएन, पैडर्म, क्वाड्रिम, केटी 5 और बेटेनोवेट जैसी चर्चित क्रीमों का उपयोग कर रहे थे। मरीजों ने स्वीकार किया कि वे ये क्रीम मेडिकल स्टोर संचालकों, रिश्तेदारों या किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति (झोलाछाप) की सलाह पर खरीद रहे थे। शुरूआत में इन क्रीमों से राहत महसूस होती थी, लेकिन जैसे ही इनका इस्तेमाल बंद किया जाता, समस्या पहले से भी अधिक गंभीर होकर उभर आती थी।

ओलावृष्टि से 200 बीघा धान की फसल तबाह, किसानों ने मांगी राहत

वेब वार्ता, शाहजहाँपुर(जलालाबाद) : बुधवार रात अचानक बदले मौसम ने जलालाबाद क्षेत्र के ग्राम सनखड़ा में भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ हुई भीषण ओलावृष्टि से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया।



चिंता की लकड़ीं गहरा गई हैं।

आजीविका पर आए इस संकट को देखते हुए पीड़ित किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को तहसील मुख्यालय पहुंचा। किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द नुकसान का पारदर्शी सर्वे करने और उचित मुआवजा देने की गुहार लगाई। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से शिवशरण, रवि शरण, सत्य शरण, यादवेंद्र, मानवेंद्र और राघवेंद्र सहित अन्य किसान मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि अगर समय पर आर्थिक सहायता नहीं मिली, तो उनके सामने जीवन–यापन का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं उप जिला अधिकारी मधुसूदन गुप्ता ने बताया कि संबंधित लेखपाल को सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है.

कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में दो वेंटिलेटर जल्द लगेंगे

वेब वार्ता, कुशीनगर।

कुशीनगर जिले में मेडिकल कॉलेज में गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधा जल्द बढ़ने वाली है।

कॉलेज के 20 बेड वाले गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में दो नए वेंटिलेटर लगाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कराने की तैयारी है। नए वेंटिलेटर शुरू होने के

बाद आईसीयू में इनकी संख्या चार हो जाएगी। इनके संचालन के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों और टेक्नीशियन की तैनाती भी की जाएगी।

मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर 20 बेड का आईसीयू संचालित है। यहां गंभीर मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जाता है। वर्तमान में दो वेंटिलेटर उपलब्ध होने के कारण एक साथ दो से अधिक अति गंभीर मरीज आने पर उन्हें उच्च चिकित्सा

छह दिनों में 19 गंभीर मरीज भर्ती, चार रेफर

केंद्र रेफर करना पड़ता है। नए वेंटिलेटर लगने से ऐसे मरीजों के इलाज में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।

हालांकि 20 बेड के आईसीयू के लिए मानक के अनुसार कम से कम 10 वेंटिलेटर की आवश्यकता बताई

जा रही है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में वेंटिलेटर की संख्या और बढ़ाई जाएगी। मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में एक से छह अक्तूबर के बीच गंभीर हालत में 19 मरीज भर्ती किए गए। इनमें से चार मरीजों को हालत अधिक गंभीर होने पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। आईसीयू में संचालित एसआईसीयू और आईसीसीयू में मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के

प्राचार्य डॉ. केपी गोड़,ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आईसीयू में वर्तमान में दो वेंटिलेटर सक्रिय हैं। जल्द ही दो नए वेंटिलेटर और लगाए जाएंगे। इनके संचालन के लिए डॉक्टर और टेक्नीशियन की तैनाती की जाएगी। इस संबंध में सीएमएस दिलीप कुमार का कहना है कि दो नए वेंटिलेटर मिलने से गंभीर मरीजों को भर्ती कर इलाज करने में सुविधा होगी।

चुनाव आयोग के खिलाफ वाम मोर्चा का पैदल मार्च जोरदार प्रदर्शन



केवल मतदाता सूचियों के विशेष गहन पनरीक्षण (एसआईआर) तक सीमित नहीं हैं। तीन चुनाव आयुक्तों में से दो ने कम से कम 14 मौकों पर मतदाता पंजीकरण, नाम

हटाने और नाम बहाल करने तथा एसआईआर के संचालन से संबंधित फैसलों पर आपत्तियां दर्ज की हैं। उन्होंने अपनी सहमति के बिना लिए जा रहे फैसलों को लेकर

इनकी रही उपस्थिति

राष्ट्रपति को संबोधित जापन के माध्यम से ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से तुरन्त हटाए जाने एसआईआर प्रक्रिया को रोकने मतदाता सूचियों से गलत तरीके से बाहर किए गए सभी लोगों के मतदान अधिकार बहाल किए जाने सहित आधा दर्जन मांगों को उजागर किया गया है इस अवसर पर सीपीआई के कामरेड राम किशोर रस्तोगी, वाला कश्यप, प्रदीप सैनी, पुष्पा सैनी, अब्दुल गफ्फर भाकपा माले के कामरेड रोहिताश राजपूत, लता सागर, परवीन जहां, संतोष वर्मा, बहादुर अली, सीपीआईएम के थान सिंह, चंद्रपाल सिंह आजाद, शरीफ अहमद, महिपाल सिंह एडवोकेट, शहाबुद्दीन, राजा हुसैन, सुनील सक्सेना, भूकन सिंह, श्याम लाल, जुम्फुंकार सैफी, राविक हुसैन, ताहिर अंसारी, डॉ हनीफ पाशा, डॉ अब्दुल सत्तार मीरानी, संजीव कुमार, असलम, एस यू सी आई सी के विजयपाल सिंह, अविनाश चंद्र, रंजन कुमार, इस्लाम अली, आदि मौजूद रहे।

भी गंभीर चिंताएं जताई हैं।

इन तमाम खुलासों से विपक्षी दलों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बार-बार उठाई गई चिंताओं की पुष्टि होती है और एसआईआर

कानपुर नगर में 2531 ईवी वाहनो को दी गई सब्सिडी

रूप में एक लाख रुपए सरकार दे रही थी, जोकि वाहन के खरीदने के बाद वाहन स्वामी के खते में एक लाख की सब्सिडी भेजी जा रही थी,लेकिन लक्ष्य पूरा होते ही सरकार ने ईवी कारो पर पूरी तरह से सब्सिडी को हटा दिया है। उन्होंने बताया कि

गुसाई मठ की जमीन पर कथित कब्जे का आरोप, पुराने अभिलेखों से खुलेगा राज

वेब वार्ता, ललितपुर। जिले के ऐतिहासिक गुसाई मठ की भूमि पर कथित कब्जे और निर्माण को लेकर मामला सामने आया है। इस संबंध में जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।

मोहल्ला चौबान्या निवासी रामेश्वर मालवीय ने शिकायत में मांग की है कि भूमि से जुड़े 1978 के न्यायालय आदेश संख्या 131/1978, पुराने राजस्व अभिलेख, नगरग्राम अभिलेख और नक्शों की जांच

ईवी सब्सिडी योजना 14 अक्टूबर, 2022 से शुरू हुई थी।14 अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च ,2025 तक मुख्यालय से आवेदक के खाते में कार्यालय स्तर से स्वीकृती मिलने के बाद राशि उनके खाते में भेज दी जाती थी।अप्रैल 2025 से कार्यालय लेवल से सभी ईवी वाहन स्वामियों के खाते में राशि भेजे जाने लगी थी। 16 अप्रैल 2025 से 1 सितम्बर ,2026 तक 1569 वाहनो को सब्सिडी भेजी जा चुकी है। 593

दोपहिया वाहन स्वामियों 2965000 रुपए का भुगतान व 976 चौपहिया वाहन स्वामियों को 97600000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं कानपुर नगर में 14 अक्टूबर 2022 से 01 सितम्बर, 2026 तक कुल 2531 वाहनो को सब्सिडीदी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में 25 हजार कारो का लक्ष्य पूरा हो जाने के बाद अब ईवी कारो पर पूरी तरह से सब्सिडी को सरकार द्वारा हटा दिया गया है।



कर वर्तमान स्थिति से मिलान कराया जाए। शिकायतकर्ता ने प्रशासनिक एवं राजस्व अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर मौके का स्थलीय निरीक्षण और

विधिवत सीमांकन कराने की भी मांग की है। उनका कहना है कि अभिलेखों और मौके की स्थिति के मिलान के बाद ही भूमि पर कथित कब्जे और निर्माण की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी। यदि जांच में सरकारी या धार्मिक भूमि पर अवैध कब्जा अथवा निर्माण प्रमाणित होता है, तो नियमानुसार कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। अब जिला प्रशासन की जांच और रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हैं।

सभी प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे

कार्यक्रम में श्री प्रेम नारायण सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशा.), देवरिया, उप जिलाधिकारी श्री अखिलेश कुमार सिंह , वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट देवरिया श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया श्री के .के.राम,जनगणना निदेशालय के प्रतिनिधि /मास्टर ट्रेनर श्रीश मिश्रा, मास्टर ट्रेनर जिला जनगणना कार्यालय देवरिया के प्रतिनिधि श्री सुरेश चंद्र जायसवाल, संतोष कुमार विश्वकर्मा प्रदीप कुमार, विनय कुमार , अखिलेश एवं फील्ड ट्रेनर श्री जय प्रकाश यादव , दीपक प्रजापति, अशोक कुमार, गोविंद मिश्रा, ओम ओमप्रकाश सहित सभी प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे।

जनपद में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 08 से 10 अक्टूबर 2026 तथा 13 से 15 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान जनसंख्या

गणना की प्रक्रिया, आंकड़ों की सही प्रविष्टि तथा फील्ड में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है।

अब कुशीनगर के ग्रामीण इलाको तक पहुंचेगी रोड बसें

वर्ष 2013 में बना था पडरौना डिपो

वेब वार्ता, कुशीनगर। कुशीनगर जिले में नगरीय इलाकों तक रोडवेज बसों के संचलन की सुविधा होने के बाद परिवहन निगम अब ग्रामीण इलाकों में बस की सुविधा मुहैया कराने की तैयारी में है। विभाग का मानना है कि इससे शहर व गांव के बीच की दूरी कम होगी और लोगों को सहूलियत मिलेगी। निगम की आमदनी में भी इजाफा होगा। परिवहन निगम ने प्रमुख इलाकों को चिन्हित कर शासन को पत्र भेजा है जिससे कि इन जगहों पर शीघ्र बसों का संचलन शुरू कराया जा सके।

जिला व तहसील मुख्यालयों के बाद परिवहन निगम का प्रयास अब ब्लाक मुख्यालय से बस सेवा शुरू करने को है। सरकारी बसों के पहिये अब उन जगहों तक पहुंचेंगे जहां बसों की सुविधा नहीं थी। परिवहन निगम की तरफ से इस आशय का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। सकारात्मक संकेत मिलने के बाद विभाग को उम्मीद है कि जल्द ही जिले के सभी 14 ब्लाक मुख्यालयों तथा अन्य प्रमुख कस्बों से भी सरकारी बसों की सेवा शुरू हो जाएगी।

इस संबंध में कुशीनगर के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जयप्रकाश

प्रधान ने बताया कि परिवहन निगम की प्राथमिकता अब पिछड़े क्षेत्रों में भी लोगों को सुगम यात्रा की सुविधा मुहैया कराना है। इसे देखते हुए ब्लाक मुख्यालयों को बस सेवा से जोड़ने की कवायद चल रही है। बीते दिनों शासन को प्रस्ताव भेजकर ब्लाक मुख्यालयों से बस सेवा शुरू करने की अनुमति मांगी गई थी, जिस पर शासन का रुख सकारात्मक है। अब तक जिला मुख्यालय तथा तहसील मुख्यालय तक बस की सुविधा थी।

50 परिचालक तथा 54 चालक हैं

पडरौना डिपो में 21 बड़ी तथा 14 छोटी सहित कुल 35 बसों का संचलन होता है। इसमें गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर व दिल्ली के लिए नियमित सेवाएं हैं, जबकि गोंडा, उन्नाव, बाँदा, बहराइच, कानपुर सहित आधा दर्जन डिपो की बसें नियमित रूप से यहां पहुंचती हैं। वर्ष 2013 में पडरौना डिपो की स्थापना हुई थी। इससे पहले यहां बसों के संचलन की जिम्मेदारी देवरिया डिपो के तहत थी। डिपो में नियमित व सॉविदा पर तैनात 50 परिचालक तथा 54 चालक हैं।

अपारदर्शी और केंद्रीकृत नियंत्रण वाली प्रक्रियाओं के कारण चुनाव व्यवस्था में जनता का विश्वास कमजोर हुआ है। लेकिन खेद का विषय है कि केंद्र सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को जवाबदेह ठहराने के बजाय, अपने अधीन दिल्ली पुलिस के द्वारा विपक्षी दलों, नागरिक समाज संगठनों और छात्र यूनियनों के प्रदर्शनकारियों पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियाँ कर रही है। यहां तक कि महिला प्रदर्शनकारियों और महिला पत्रकारों के साथ अश्लीलतापूर्ण हरकत एवं उत्पीड़न किया जा रहा है।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी



नई दिल्ली। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी है। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों और मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), वाम दलों समेत कई अन्य विपक्षी दलों के भी प्रदर्शन में शामिल होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज दिल्ली पहुंच रही हैं। कांग्रेस ने 6 और 7 अक्टूबर को हुए प्रदर्शनों के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा को हिरासत में लिए जाने तथा कथित बदसलूकी के विरोध में गुरुवार को ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। बुधवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जंतर-मंतर के पास प्रदर्शन में हिस्सा लिया था।

दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजघाट पर दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किए हैं। इसके अलावा बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

पटना में तेजस्वी ने शुरु किया मार्च

बिहार की राजधानी पटना में भी एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। आरजेडी के एक प्रतिनिधिमंडल को पुलिस राजभवन ले गई। कांग्रेस नेताओं के लिए प्रदर्शन में शामिल होने का समय सुबह 11 बजे तय था, लेकिन तेजस्वी यादव उससे पहले ही मार्च शुरू कर चुके थे। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ता भी बिहार विधानसभा के सामने शहीद स्मारक के पास पहुंचे। यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ कुछ आरजेडी और वाम दलों के कार्यकर्ता भी पार्टी झंडों के साथ नजर आए।

बेंगलुरु में सीजेपी का प्रदर्शन

बेंगलुरु में कॉंग्रेसव जनता पार्टी (सीजेपी) भी एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अभिनेता प्रकाश राज के नेतृत्व में पीपल्स ट्रिब्यूनल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एसआईआर को लेकर लोगों की चिंताओं और शिकायतों को सामने रखा जाएगा। सीजेपी का मुख्य प्रदर्शन शाम 4 बजे से प्रस्तावित है।

रूस और ईरान पर अमेरिकी दांव उल्टा पड़ा, भारत ने ठुकराई फ्री ट्रेड डील



नई दिल्ली। अमेरिका का भारत पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाने का दांव पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। रूस और ईरान पर शिंकजा कसने के बहाने भारत-रूस संबंधों को निशाना बनाने चली अमेरिकी प्रशासन की नीतियों ने खुद भारत-अमेरिका फ्री ट्रेड डील की बलि ले ली है। पाबंदियों की तलवार लटकाकर व्यापार समझौते की उम्मीद कर रहे अमेरिका को भारत ने कड़ा संदेश दिया है और दबाव में आकर कोई भी सौदा करने से साफ इनकार कर दिया है। भू-राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को धमकियों से झुकाने की वॉशिंगटन की पुरानी नीति अब पूरी तरह उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने रूस और ईरान पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से एक कानून का सहारा लिया था, जिसका मुख्य मकसद भारत और रूस की दशकों पुरानी रणनीतिक और आर्थिक दोस्ती में दरार डालना था।

अमेरिका चाहता था कि भारत किसी भी कीमत पर रूस से कच्चा तेल और रक्षा उपकरण खरीदना बंद कर दे। इस कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल गया था कि वह रूस से व्यापार करने वाले देशों के सामान पर भारी-भरकम पेंसल्टी टैरिफ लगा सकते हैं। वॉशिंगटन को लगता था कि वह इस आर्थिक डर का इस्तेमाल करके भारत को अपने पाले में झुका लेगा, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता के मामले में किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका का यह रुख न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि उसकी कूटनीतिक नाकामी और दोहरे मापदंडों को भी बेनकाब करता है। जमीनी हकीकत यह है कि मौजूदा वैश्विक संकट के दौरान भारत ने ही अमेरिकी ऊर्जा बजार को एक बड़ा सबक दिया है और हाल के महीनों में भारत अमेरिकी लिविंगफाइंड नेचुरल गैस (एलएनजी) का एक प्रमुख खरीदार बनकर उभरा है। इसके बावजूद अमेरिका द्वारा भारत को निशाना बनाया जाना समझ से परे है, जबकि रूस से सबसे ज्यादा ऊर्जा आयात करने वाले अन्य देश भी शामिल हैं जिन पर अमेरिका का रवैया नरम रहता है। अमेरिका की असल मंशा यह है कि भारत अपने कृषि, डिजिटल और औद्योगिक क्षेत्रों को अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए पूरी तरह खोल दे, लेकिन भारत के लिए अपने करोड़ों किसानों, छोटे व्यापारियों और घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

राहुल और दीपके के आंदोलनों में बढ़ी खींचतान

चुनाव आयोग पर आरोपों का नया दौर

नई दिल्ली। हाल के वर्षों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी के आरोप लगाते रहे हैं। उनके इन आरोपों को उस समय और बल मिला जब एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनके दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति का दावा किया गया। हालांकि, चुनाव आयोग ने बिना देरी किए इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन नीट पेपर लीक आंदोलन से सुर्खियों में आई कॉंग्रेसव जनता पार्टी ने इस मुद्दे को तुरंत भुनाने की कोशिश की। तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मदे प्रधान के इस्तीफे से उत्साहित अभिजीत दीपके ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी और तत्काल



आंदोलन का ऐलान कर दिया। कॉंग्रेसव जनता पार्टी और कांग्रेस के मुद्दे भले ही एक जैसे हों, लेकिन दोनों ही दल एक-दूसरे का खुलकर साथ देने से कतरा रहे हैं। अभिजीत दीपके जब जंतर-मंतर पर धर्मदे प्रधान का श्रेय लेने की भी कोशिश की, हालांकि कई विपक्षी दल इसे कॉंग्रेसव जनता पार्टी और



राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देकर विपक्षी दलों को भी चौंका दिया था। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के इस कार्यक्रम की चर्चा बाकी विपक्षी दलों से नहीं की गई थी। बाद में उन्होंने धर्मदे प्रधान से नहीं निकलने देना चाहती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख

अभिजीत दीपके की ही जीत मानते हैं। कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस मामले पर कोई भी चुक करना नहीं चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ तमाम विपक्षी दल 2014 में केंद्र में भाजपा के आने के बाद से लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते आ रहे हैं। उनका दावा है कि ईवीएम के जरिए वोटों की हेराफेरी की जाती है। हालांकि, चुनाव आयोग इन आरोपों को लगातार झुटलाता रहा है। अब जब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ माहिल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो कांग्रेस अपने उन पुराने आरोपों के दम पर इस आंदोलन को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख

अपना लिया है। उन्होंने लगातार दो दिनों तक इस मुद्दे पर आंदोलन किया और जंतर-मंतर जाने की कोशिश की। दोनों को उससे पहले ही हिरासत में ले लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा ने इस मामले में विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी चौंका दिया है। बुधवार को जब दोनों आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ के नीचे बैठ गए, तो उनके साथ किसी दूसरे दल के नेता नहीं दिखे। कहा गया कि किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। एक विपक्षी नेता ने तो नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को भाई-बहन का शो बनाना चाहती है। दूसरी ओर, ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर अभिजीत दीपके फिलहाल पिछड़े नजर आ रहे हैं।

वेटा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने महिला लड़ाकों की एक नई इकाई बनाने का दावा किया है। संगठन की ओर से जारी वीडियो में कुछ महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण लेते और हथियारों के साथ गतिविधियों में शामिल होते दिखाया गया है। बीएलएफ ने इस इकाई का नाम करीमा आम्द अर्साद डिवीजन (केएएडी) रखा है। वीडियो और संगठन की ओर से किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट में बीएलएफ के मुताबिक नई इकाई में शामिल महिलाओं को केवल सशस्त्र गतिविधियों तक सीमित नहीं रखा गया है। वे खुफिया जानकारी जुटाने, संचार, चिकित्सा सहायता और रसद संबंधी कार्यों में भी भूमिका निभा सकती हैं। इस इकाई का नाम करीमा



बलोच के नाम पर रखा है, जो बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन-आजाद की पूर्व अध्यक्ष थीं और बलूच अलगाववादी आंदोलन से जुड़ी थीं। संगठन ने दावा किया है कि केएएडी से जुड़ी महिला सदस्यों ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में

गतिविधियां की हैं। बीएलएफ की ओर से तुरन्त के पास चीन-पाकिस्तान आर्थिक गिलियार से जुड़े मार्ग पर पाकिस्तानी सैन्य काफिले को निशाना बनाने और कुछ सैन्यकर्मियों के मारे जाने का दावा भी किया गया है।

प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, राहुल-प्रियंका समेत कई नेताओं पर एफआईआर

पुलिस ने अब तक तीन मामले दर्ज किए, मारपीट, सरकारी काम में बाधा और बदसलूकी समेत कई धाराएं लगाईं

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को हुए प्रदर्शन के सिलसिले में पुलिस ने अब तक तीन एफआईआर दर्ज की हैं।

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में कुछ और एफआईआर भी दर्ज की जा रही हैं। दर्ज मामलों में पुलिसकर्मियों के साथ कथित मारपीट, सरकारी काम में बाधा, धक्का-मुक्की और पुलिसकर्मियों से बदसलूकी से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं। एफआईआर में

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा के नाम भी शामिल हैं। यह कार्रवाई उस समय हुई जब इंडिया ब्लॉक के सांसद जंतर-मंतर की ओर मार्च कर रहे थे। विपक्षी सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने जा रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे। राहुल गांधी ने बैरिकेड खोलने की कोशिश की प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। राहुल गांधी को बाराखंभा रोड पुलिस



स्टेशन ले जाया गया। इस दौरान वह प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड के गेट को खोलने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। बाद में हिरासत में लिए जाने के दौरान उन्होंने

सड़क पर लेटी नजर आई। प्रियंका ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे सांसदों के खिलाफ पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया। सविधान के लिए जान देने को तैयार पुलिस वाहन से सविधान की प्रति दिखाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में सविधान की क्या कीमत रह गई है। उन्होंने कहा कि सविधान की रक्षा के लिए वे अपनी जान तक देने को तैयार हैं। राहुल बोले- प्रदर्शन जारी रहेगा राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक सविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर बार-बार सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष

गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी तैयार है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के बीच गठजोड़ सामने आ चुका है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, विपक्ष का आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बुधवार के प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई और पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की तथा बदसलूकी की गई। इसी आधार पर पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं और घटनाक्रम से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत की नई पहल

ट्रंप जो न कर सके, अब दिल्ली बनाएगी मुमकिन

नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को अब चार साल से अधिक का समय जा चुका है, इस जंग ने लाखों लोगों की जान ली है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को गंभीर रूप से बाधित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को रोकने के लिए अपने दूसरे कार्यकाल में कई कूटनीतिक और धमकी भरे प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब इस खूनी जंग को समाप्त करने और शांति बहाल करने के लिए भारत ने एक महत्वपूर्ण शांति प्रस्ताव दिया है।

दरअसल प्रस्ताव भारतीय विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने 3 सितंबर को यूक्रेन की अपनी पहली स्वतंत्र यात्रा के दौरान पेश किया, जहां उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेन्स्की से मुलाकात की और भारत की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा



दिया। भारत का यह तीन-सूत्रीय प्रस्ताव युद्ध के सबसे संवेदनशील और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पहलुओं पर केन्द्रित है। भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के मुताबिक ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर हमले रोकना है। दोनों पक्षों से एक-दूसरे के एनर्जी प्लांट्स और महत्वपूर्ण बुनियादी

ढांचे को निशाना न बनाने की अपील। इसके अलावा ब्लैक सी के बंदरगाहों से अनाज और ऊर्जा की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना। इतना ही नहीं ब्लैक सी में आवाजाही करने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर किसी भी हमले को तुरंत रोकना। भारत का यह प्रस्ताव अब तक

आए अन्य देशों जैसे मिस्र और तुर्की (जो मुख्य रूप से व्यापारिक जहाजों पर केन्द्रित थे) और अमेरिका (जो एनर्जी सौजन्य पर केन्द्रित था) के प्रस्तावों की तुलना में अधिक व्यावहारिक और व्यापक माना जा रहा है। भारत ने इन सभी प्रमुख चिंताओं को एक साथ रखकर एक समग्र समाधान प्रस्तुत किया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में इस युद्ध को रोकने के लिए अथक प्रयास करते रहे, कभी धमकियां दीं तो कभी बातचीत का सहारा लिया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब भारत की यह पहल न केवल वैश्विक शांति के लिए एक नई उम्मीद जगाती है, बल्कि उस जटिल चुनौती का समाधान खोजने का प्रयास करती है, जिसमें एक वैश्विक शक्ति विफल रही।

दुनिया में फिर मंडराया एक और महामारी का खतरा ?

मॉस्को। दुनिया कोरोना महामारी की भयावह यादों से अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाई है कि रूस से सामने आई एक रहस्यमय घटना ने जैव-सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। साइबेरिया के इरकुत्स्क क्षेत्र के शेलेखोव स्थित एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक दुर्घटना के बाद एक महिला कर्मचारी की रहस्यमय निमोनिया से मौत की खबर सामने आई है। घटना के बाद अधिकारियों ने मामले की जांच तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक, मृतक महिला कर्मचारी की उम्र 28 वर्ष थी। उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल

में भर्ती कराया गया था, जहां उसे निमोनिया का पता चला। हालांकि, उसकी बीमारी का वास्तविक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रयोगशाला में हुई दुर्घटना के दौरान आखिर क्या हुआ और क्या किसी खतरनाक जैविक पदार्थ के संपर्क में आने की वजह से यह संक्रमण फैला? घटना सामने आने के बाद रूस की संक्रमण नियंत्रण एजेंसी मामले की निगरानी कर रही है। अधिकारियों की ओर से फिलहाल यह पुष्टि नहीं की गई है कि प्रयोगशाला से कोई खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया बाहर निकला था।

है। इस कदम को चीन के दुर्लभ खनिजों और मैग्नेट के निर्यात पर नियंत्रण के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इससे चीन के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने चीन जाने वाले विमानन पुर्जों के निर्यात लाइसेंस पर सख्ती की है। चीन को बड़ी मात्रा में पुर्जे जमा करने से रोकने के विकल्पों पर भी अमेरिका विचार

कर रहा है। सी919 को चीन अपनी विमानन तकनीक और औद्योगिक आत्मनिर्भरता का अहम प्रतीक मानता है। यह विमान बोइंग 737 और एयरबस ए320 जैसे विमानों को टक्कर देने के उद्देश्य से विकसित की गई है और इसमें 158 से 192 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। सी919 का सबसे अहम हिस्सा अभी पूरी तरह घरेलू नहीं है। विमान में लीप-1सी इंजन लगाया जाता है, जिसे अमेरिकी कंपनी जीएई एयरोस्पेस और फ्रांस की साफ्रन के संयुक्त उपक्रम सीएफएम इंटरनेशनल द्वारा बनाया जाता है। ऐसे में अमेरिकी पुर्जों की आपूर्ति पर दबाव बढ़ने से चीन के लिए विमान का उत्पादन और परिचालन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

बोइंग 737 और एयरबस ए320 जैसे विमानों को टक्कर देने के उद्देश्य से विकसित की गई है और इसमें 158 से 192 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। सी919 का सबसे अहम हिस्सा अभी पूरी तरह घरेलू नहीं है। विमान में लीप-1सी इंजन लगाया जाता है, जिसे अमेरिकी कंपनी जीएई एयरोस्पेस और फ्रांस की साफ्रन के संयुक्त उपक्रम सीएफएम इंटरनेशनल द्वारा बनाया जाता है। ऐसे में अमेरिकी पुर्जों की आपूर्ति पर दबाव बढ़ने से चीन के लिए विमान का उत्पादन और परिचालन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत का ओआईसी पर तीखा प्रहार: पीड़ित-दोषी में फर्क समझें

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) की जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान में भारत की आतंकवाद-रोधी कार्रवाइयों पर की गई टिप्पणियों को सिर से खारिज किया, यह कहकर कि यह समूह पीड़ित और दोषी के बीच फर्क करने में असमर्थ है। पश्चिम त्रिपुरा से लोकसभा सदस्य बिल्वर कुमार देब ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के उन्मूलन के उपाय विषय पर भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देकर ओआईसी को कड़ी नसीहत दी। लोकसभा सदस्य देब ने जम्मू-कश्मीर के उल्लेख पर कड़ी आपत्ति

जताकर स्पष्ट किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई उन्हीं स्थानों से निर्देशित और योजनाबद्ध हमलों का जवाब थी। ओआईसी पर तथ्यों और कल्पनाओं के बीच अंतर न कर पाने का आरोप लगाकर उन्होंने कहा कि भारत को सीमा पार आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा का पूरा अधिकार है। उन्होंने ओआईसी द्वारा जम्मू-कश्मीर के अनुचित उल्लेख को औलोचना कर पाकिस्तान के अवेक कब्जे वाले रावलकोट पर ध्यान देने की सलाह दी, जहाँ अंधाधुंध हत्याएं और मानवाधिकारों का हनन स्पष्ट है।



ओआईसी ने अपने बयान में दक्षिण एशिया में सैन्य तनाव बढ़ने और

पाकिस्तान में अनुचित हमलों का जिक्र किया, पर भारत का नाम नहीं लिया।

भारत ने पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया था। यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल 22 अप्रैल को हुए जषन्य आतंकवादी हमले, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे, का सीधा जवाब थी। हमला पाकिस्तान स्थित दर्रेजिस्ट्रेस प्रंट ने किया था। देब ने भारत के कड़वे अनुभव को साझा कर कहा कि आतंकवाद एक लगातार और रोजमर्रा की वास्तविकता है। उन्होंने जोर दिया कि इसका हर रूप मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरा है, जो शांति, प्रगति और मानवाधिकारों को प्रभावित करता है।

दुश्मन की नाक में दम करेंगी बीएलएफ की महिला ब्रिगेड, ले रही रही खतरनाक ट्रेनिंग

वेटा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने महिला लड़ाकों की एक नई इकाई बनाने का दावा किया है। संगठन की ओर से जारी वीडियो में कुछ महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण लेते और हथियारों के साथ गतिविधियों में शामिल होते दिखाया गया है। बीएलएफ ने इस इकाई का नाम करीमा आम्द अर्साद डिवीजन (केएएडी) रखा है। वीडियो और संगठन की ओर से किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट में बीएलएफ के मुताबिक नई इकाई में शामिल महिलाओं को केवल सशस्त्र गतिविधियों तक सीमित नहीं रखा गया है। वे खुफिया जानकारी जुटाने, संचार, चिकित्सा सहायता और रसद संबंधी कार्यों में भी भूमिका निभा सकती हैं। इस इकाई का नाम करीमा



बलोच के नाम पर रखा है, जो बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन-आजाद की पूर्व अध्यक्ष थीं और बलूच अलगाववादी आंदोलन से जुड़ी थीं। संगठन ने दावा किया है कि केएएडी से जुड़ी महिला सदस्यों ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में

गतिविधियां की हैं। बीएलएफ की ओर से तुरन्त के पास चीन-पाकिस्तान आर्थिक गिलियार से जुड़े मार्ग पर पाकिस्तानी सैन्य काफिले को निशाना बनाने और कुछ सैन्यकर्मियों के मारे जाने का दावा भी किया गया है।

पत्रकार स्व. पंकज शर्मा की प्रतिमा का उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया अनावरण

रायपुर। अपनी निर्भीक पत्रकारिता, प्रभावशाली लेखनी और संवाद क्षमता के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पहचान देश-विदेश तक पहुंचाने वाले वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय पंकज शर्मा को उनकी जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। 6 अक्टूबर को उनकी जयंती के अवसर पर खो-खो पारा स्थित पंकज उद्यान में उनकी प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें स्मरण किया गया। रायपुर की पत्रकारिता परंपरा के इस समर्पित हस्ताक्षर की स्मृति को स्थायी स्वरूप देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन रायपुर प्रेस क्लब, अखंड ब्राह्मण समाज छत्तीसगढ़ और विप्र सांस्कृतिक भवन प्रबंधन समिति के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। समारोह में वकाओं ने पंकज शर्मा के अल्प जीवनकाल में पत्रकारिता के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान को याद किया और कहा कि उनकी पत्रकारिता आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय पंकज शर्मा ने पत्रकारिता को केवल पेशे के रूप में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और मिशन के रूप में जिया। उन्होंने अपने अल्प जीवनकाल में पत्रकारिता के क्षेत्र



रायपुर की गौरवशाली पत्रकारिता परंपरा के प्रतिनिधि श्रे पंकज शर्मा : बृजमोहन अग्रवाल

में जो योगदान दिया, वह आज भी पत्रकारों और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है। उनकी स्मृति में प्रतिमा की स्थापना रायपुर की गौरवशाली पत्रकारिता परंपरा के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

पंकज शर्मा की स्मृति पत्रकारिता की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा : मोहन तिवारी

रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी ने कहा कि पंकज शर्मा जैसे पत्रकार पत्रकारिता की उस समृद्ध परंपरा का हिस्सा हैं, जिसने रायपुर को राष्ट्रीय पत्रकारिता के मानचित्र पर विशिष्ट पहचान दिलाई। उनकी स्मृति में प्रतिमा की

स्थापना आने वाली पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित कराने का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि रायपुर प्रेस क्लब इस आयोजन का हिस्सा बनकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। उन्होंने कहा कि रायपुर से पत्रकारिता के क्षेत्र में देश और प्रदेश में पहचान बनाने वाले ख्यातनाम पत्रकारों के योगदान को याद करने की परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए पुण्य स्मरण—पुरखा के सुरुता की भावना के साथ पत्रकारिता के पुरखों को याद करने की पहल को आगे ले जाने की बात कही। **प्रेस क्लब के पदाधिकारी और पत्रकार रहे मौजूद** कार्यक्रम में रायपुर प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष दिलीप साहू, महासचिव गौरव शर्मा, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, संयुक्त सचिव निवेदिता साहू एवं भूपेश जांगड़े सहित वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी, प्रशांत शर्मा, मंनजुसा शर्मा वैभव पांडे, सनत तिवारी, बल्लू तिवारी, देवेश तिवारी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने न केवल स्वर्गीय पंकज शर्मा की स्मृतियों को जीवंत किया, बल्कि रायपुर की समृद्ध पत्रकारिता परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के संकल्प को भी मजबूती दी।

छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धियों से भरा रहा सीएम का सिंगापुर दौरा

43,600 करोड़ की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबद्धताएं कौशल विकास समझौता और वैश्विक साझेदारियां



रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर की सफल यात्रा के बाद आज रायपुर लौटा। तीन दिवसीय इस दौरे में प्रदेश को २43,600 करोड़ की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुईं। किसी एक विदेश यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ को मिले यह अब तक के सबसे बड़े निवेश प्रतिबद्धताओं में शामिल हैं।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रथम 'सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ फोरम-2026' में भागीदारी के लिए देश से केवल छत्तीसगढ़ और हरियाणा का चयन किया गया था। सिंगापुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ ने २41,750 करोड़ के एआई-रेडी डेटा सेंटर कैपेस के निवेश प्रस्ताव के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में ITE Education Services, Singapore के साथ महत्वपूर्ण एमओयू किया। वहीं Gardens by the Bay और Mandai Wildlife Group जैसी विश्वस्तरीय संस्थाओं के साथ हरित विकास, पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

एआई डेटा सेंटर से सौर ऊर्जा और कृषि प्रसंस्करण तक बड़े निवेश सिंगापुर की Energy Capital Global (ECG) ने छत्तीसगढ़ में 100 मेगावाट क्षमता का एआई-रेडी डेटा सेंटर कैपेस विकसित करने के लिए २41,750 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। यह परियोजना प्रदेश को देश की उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधुनिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ी पहल साबित हो सकती है।

इसी प्रकार Sunstream Green Energy Pvt. Ltd. को सोलर क्षेत्र के साथ साथ 300 मेगावाट की सम्बन्धित बैटरी स्टोरेज और कंपोनेंट्स के लिए २1,500 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव भी प्रस्ताव हुआ। वहीं 22 देशों में कार्यरत वैश्विक एग्रीबिजनेस समूह को 350 करोड़ के

एकीकृत एग्री एवं फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए निवेश आमंत्रण दिया गया। इससे प्रदेश में कृषि उत्पादों की वैल्यू चेन मजबूत होने के साथ किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के नए अवसर बनेंगे। इन निवेश प्रस्तावों का लाभ प्रदेश के विभिन्न वर्गों तक पहुंचेगा। युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई-टेक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक उद्योगों में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। स्थानीय स्टार्टअप और एमएसएमई को बड़ी वैश्विक कंपनियों के सप्लायर और बिजनेस पार्टनर के रूप में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, वहीं प्रदेश के किसानों और कृषि उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजार तक बढ़ेगी।

युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप मिलेगा कौशल प्रशिक्षण भविष्य के उद्योगों के लिए प्रदेश के युवाओं को तैयार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने ITE Education Services, Singapore के साथ इस प्रकार Sunstream Green Energy Pvt. Ltd. को सोलर क्षेत्र के साथ साथ 300 मेगावाट की सम्बन्धित बैटरी स्टोरेज और कंपोनेंट्स के लिए २1,500 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव भी प्रस्ताव हुआ। वहीं 22 देशों में कार्यरत वैश्विक एग्रीबिजनेस समूह को 350 करोड़ के

SING Forum में दुनिया के सामने रखी छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा Singapore Business Federation (SBF) द्वारा आयोजित SING Forum-2026 में छत्तीसगढ़ ने निवेश, उद्योग और विकास के क्षेत्र में अपनी नई संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। फोरम में सिंगापुर की विदेश मंत्रालय तथा व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री सुश्री फोर्मेस के दौरान आयोजित 'फायरसाइड चैट' में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुधारों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि प्रदेश में आने वाला प्रत्येक निवेश रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का माध्यम बने।

सिंगापुर के विदेश मंत्री से मुलाकात, राज्य स्तर पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा मुख्यमंत्री श्री साय ने सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. Vivian Balakrishnan से तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एमओयू किया। इसके अंतर्गत उद्योगों की जरूरत के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने, तकनीकी प्रशिक्षण को मजबूत करने और युवाओं के लिए कौशल से रोजगार तक बेहतर अवसर विकसित करने पर काम किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का किया शुभारंभ

बहतराई की खेल भूमि ने देश को दिए कई प्रतिभावान खिलाड़ी : अरुण साव



रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने आज बिलासपुर के स्वर्गीय बी.आर. यादव राज्य प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई में 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश के पांचों संभागों से आए खिलाड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी ली और गुब्बारे छोड़कर प्रतियोगिता का आगाज किया। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में बस्तर, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग के 571 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 10 अक्टूबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में 14 वर्ष, 17 वर्ष एवं 19 वर्ष आयु वर्ग की तीरंदाजी, 19 वर्ष आयु वर्ग की हॉकी और 19 वर्ष बालक वर्ग की कबड्डी के मुकाबले बहतराई के एस्टोर्टफ, इंडोर स्टेडियम और तीरंदाजी मैदान में खेले जाएंगे। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने शुभारंभ कार्यक्रम में खिलाड़ियों का

उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बहतराई की खेल भूमि ने देश और प्रदेश को कई प्रतिभावान खिलाड़ी दिए हैं। इसी मैदान पर खेलकर संजू देवी ने एशियन गेम्स कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। मधु सिदार और गीता यादव ने अंडर-19 महिला हॉकी में देश को गौरवान्वित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संदेश 'जो खेलेगा वही खिलेगा' को दोहराते हुए खिलाड़ियों से पूरी खेल भावना और आत्मविश्वास के साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बेततरा विधायक श्री सुशान्त शुक्ला ने कहा कि खेल के

मैदान में कोई हारता नहीं है, खिलाड़ी या तो जीतता है या सीखता है। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर संसाधन और सुविधाएं जरूरी हैं। उन्होंने बहतराई खेल परिसर को मध्य भारत के उत्कृष्ट खेल संस्थानों में विकसित करने के लिए इसके उन्नयन पर जोर दिया।

बिलासपुर के कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, नगर निगम के आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्व, जिला पंचायत के सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, श्री दीपक सिंह, श्री मोहित जायसवाल और जिला शिक्षा अधिकारी श्री संदीप पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, खिलाड़ी एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित थे। पीएमश्री कन्या विद्यालय सरकंडा की छात्राओं ने शुभारंभ कार्यक्रम में भारत माता की वंदना सहित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। तपती धूप में छात्राओं की शानदार प्रस्तुति की अतिथियों ने सराहना की।

राज्य स्तरीय रोजगार मेले के पहले दिन 5,018 प्रतिभागियों ने कराया पंजीयन

85 संस्थानों की प्रारंभिक चयन प्रक्रिया में दो हजार से अधिक अभ्यर्थियों का चयन



रायपुर। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर और सुनहरे अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले के पहले दिन युवाओं में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। मेले के पहले दिन विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे कुल 5,018 प्रतिभागियों ने अपना पंजीयन कराया, जिसमें से 85 निजी संस्थानों द्वारा की गई प्रारंभिक चयन प्रक्रिया के माध्यम से दो हजार से अधिक अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। इस राज्य स्तरीय मेले में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश कर रहे युवा पहुंचे। कौशल और योग्यता के आधार पर चयन निजी क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों द्वारा उपलब्ध रिक्त

पदों के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, कौशल और अनुभव के आधार पर प्रारंभिक चयन प्रक्रिया पूरी की गई। युवाओं ने अपनी रुचि के अनुसार साक्षात्कार और अन्य चयन प्रक्रियाओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार प्रदाता संस्थानों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को एक ही मंच पर जोड़ने का बेहतरीन प्रयास किया गया है, जिससे युवाओं को सीधे चयन प्रक्रिया में शामिल होने का सीधा अवसर मिला।

पशुओं को देख उप मुख्यमंत्री शर्मा ने अधिकारियों को लगाई फटकार

देर रात हाइवे पेट्रोलिंग वाहन बुलाकर मौके पर ही ली रैस्क्यू और नियमित निरीक्षण की जानकारी

सड़क पर गौवंश की सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नियमित पेट्रोलिंग के सख्त निर्देश



ऑपरेशन के साथ ही प्रतिदिन किए जा रहे निरीक्षण एवं अन्य कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कवर्था से बेमतरा तक पड़ने वाले ग्रामों के स्थानीय लोगों के माध्यम से पेट्रोलिंग वाहन की गतिविधियों की नियमित जानकारी ली जाए। सड़क पर पशुओं की मौजूदगी को लेकर उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि हाइवे पर नियमित पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए और सड़क पर बैठे अश्वत्थ विचरण कर रहे पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कार्रवाई तत्परता से की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। शर्मा ने कहा कि सड़क पर पशुओं के रहने से न केवल गौवंश की जान को खतरा रहता है, बल्कि वाहन चालकों और यात्रियों के लिए भी गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

मुख्य सचिवों के सम्मेलन के लिए छत्तीसगढ़ की प्राथमिकताओं को तय किया विकास शील ने



रायपुर। 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की प्राप्ति में छत्तीसगढ़ की भूमिका और राज्य की प्राथमिकताओं को तय करने के लिए आज मंत्रालय में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में छठवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन के लिए विभिन्न विभागों की प्रस्तुतियों और प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला के दौरान आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए निवेश, रोजगार, नागरिक सेवाओं का विस्तार और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाना है। ग्रामीण विकास प्रबंधन (रूरल कनेक्टिविटी), जल संरक्षण और ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करना। मुख्य

सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं के लक्ष्य अधिक ठोस, स्पष्ट और सम्यक् माइलस्टोन (समय-सीमा) के साथ होने ताकि नागरिकों के जीवन पर इनके सकारात्मक प्रभावों का सटीक आकलन किया जा सके। खनिज सचिव पी. दयानंद ने महत्वपूर्ण खनिजों के विकास और उनसे जुड़ी संभावनाओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

सड़कों के काम युद्धस्तर पर शुरू करने की तैयारी पीडब्लूडी ने 4 कार्यों की निविदा को दी मंजूरी

कुल 145.28 करोड़ की लागत से होंगे सड़कों के उन्नयन, चौड़ीकरण और विद्युतीकरण के काम, नई सड़क भी बनेगी



रायपुर। बरसात के बाद राज्य में सड़कों के काम युद्धस्तर पर शुरू होंगे। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए निविदा प्रक्रिया तत्परता से पूर्ण कर कई कार्यों के लिए निविदा को मंजूरी प्रदान की है। विभाग ने रायगढ़ जिले में 4 कार्यों के लिए कुल 145 करोड़ 27 लाख 56 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। इनमें दो सड़कों के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण, एक सड़क के उन्नयन तथा एक सड़क के निर्माण का काम शामिल है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने इन कार्यों की निविदा मंजूर करते हुए रायगढ़ संभाग के कार्यालय अभियंता को चयनित ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों को कार्यदेश जारी कर तत्काल कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। लोईगं-महापल्ली मुख्य जिला मार्ग में पांच किलोमीटर हिस्से के फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए 59 करोड़ 49 लाख 4 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। रायगढ़-कोतरा-नंदेली राज्य मार्ग के पांच किलोमीटर हिस्से में फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए भी 47 करोड़ 77 लाख 76 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है। विभाग द्वारा 3.40 किलोमीटर उर्दना-कृष्णापुर-खैरपुर मार्ग के निर्माण लिए

13 करोड़ 74 लाख 29 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है। कोझातराई-पुसौर-सूरजगढ़ सड़क में 12.30 किलोमीटर लंबाई के फोरलेन में उन्नयन के लिए 24 करोड़ 26 लाख 47 हजार रुपए की निविदा लोक निर्माण विभाग ने स्वीकृत की है। इस राशि से सड़क के 8.30 किलोमीटर और 4 किलोमीटर के दो हिस्सों का फोरलेन में उन्नयन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के रायगढ़ संभाग के कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित कार्यों का संपादन और पर्यवेक्षण विभागीय मार्फतों के अनुसार सुनिश्चित करते हुए कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये कार्य किसी अन्य को सबलौट नहीं करने तथा कार्य संपादन के लिए पॉवर-ऑफ-अटॉर्नी की मान्य नहीं करने की कहा है। श्री साव ने अनुबंधित समयवधि में कार्यों को पूर्ण करने, कार्यों का संपादन अनुबंधानुसार प्रशासकीय स्वीकृति एवं आबंटन की सीमा में करने के भी निर्देश दिए हैं।

महत्त्वपूर्ण ख़बर

वर्ल्ड एथलीट ऑफ़ द ईयर पुरस्कार के दावेदारों में नीरज को नहीं मिली जगह

■ मोनाको। विश्व एथलेटिक्स ने इस साल के प्रतिष्ठित मेन्स वर्ल्ड एथलीट ऑफ़ द ईयर पुरस्कार के लिए जिन 10 शीर्ष दावेदारों के नाम तय किये हैं। उसमें भारत के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा जगह नहीं मिली है। इस सूची में श्रीलंका के भाला फेंक चैंपियन रुमेश थरंगा पथिरागो का नाम भी शामिल है। हाल के दिनों रुमेश ने काफी असफलताएं हासिल की हैं। वहीं नीरज को इस सूची में जगह न मिलना उनके प्रशंसकों के लिए एक झटका है, खासकर वोटों से जुझने के बाद। यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह 29 नवंबर को मोनाको में होगा। इसमें पुरुषों और महिलाओं के वर्गों में वर्ल्ड एथलीट ऑफ़ द ईयर विजेताओं के नामों की घोषणा होगी।

2027 एकदिवसीय विश्व कप में तीन बार हो सकता है भारत-पाकिस्तान का मुकाबला

दुबई। अगले साल 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में होने वाले एकदिवसीय विश्वकप के लिए सभी टीमों ने अपनी तैयारियों शुरू कर दी है।

यह महाकुंभ कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। इसका एक कारण ये भी है कि इसमें चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच तीन बार मुकाबला हो सकता है। यह पहला मौका होगा जब पुरुष एकदिवसीय विश्व कप में रिकॉर्ड 14 टीमों हिस्सा लेंगी और कुल 57 मुकाबले खेले जाएंगे। अफ्रीकी महाद्वीप 24 साल बाद

एकदिवसीय विश्व कप की मेजबानी कर रहा है, इससे पहले 2003 में यहां हुए टूर्नामेंट में भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी।

इस बार के टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण भारत और पाकिस्तान का एक ही ग्रुप-ए में होना है। ग्रुप-ए में इन दोनों दिग्गजों के अलावा गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, मेजबान जिम्बाब्वे और एक क्वालीफायर टीम शामिल है, जबकि ग्रुप-बी में इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और दूसरी क्वालीफायर टीम को जगह मिली है। नए फॉर्मेट के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के दिवानों को एक नहीं, बल्कि तीन बार रोमांचक भिड़ंत देखने को मिल सकती है।



पहला मुकाबला तो ग्रुप स्टेज में 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग के



ऐतिहासिक वांडरर्स स्टेडियम में तय हो चुका है। इस मैच पर दुनिया



भर को निगाहें टिकी होंगी, खासकर यह देखते हुए कि

एकदिवसीय विश्व कप के इतिहास में पाकिस्तान कभी भी भारत को हरा नहीं पाया है। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए आठ विश्व कप मुकाबलों में भारत ने अजेय बढ़त बनाई हुई है। वहीं, अगर सभी बड़े आईसीसी इवेंट्स को मिला लिया जाए, तो 23 मुकाबलों में से 19 बार भारतीय टीम विजयी रही है। ग्रुप स्टेज के बाद दूसरी भिड़ंत सुपर-7 चरण में संभव है। दोनों ग्रुप से शीर्ष टीमों इस दौर में पहुंचेंगी, जहां वे एक-दूसरे का सामना करेंगी। यदि भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर इस चरण में अपनी जगह बनाती हैं, तो प्रशंसकों को एक और हाई-वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके बाद तीसरी और सबसे रोमांचक भिड़ंत नॉकआउट यानी सेमीफाइनल या फाइनल में

संभव है। सुपर-7 चरण के बाद अंक तालिका की शीर्ष-4 टीमों सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। अगर दोनों टीमों नॉकआउट मुकाबलों में भी जीत हासिल करती हैं, तो खिताबी जंग या सेमीफाइनल में वे तीसरी बार आमने-सामने आ सकती हैं। भारतीय टीम अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत 7 अक्टूबर को केप टाउन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी, जो 2023 वनडे विश्व कप फाइनल की हार का बदला लेने का मौका होगा। इस बार कुल 12 चुनिंदा वेन्यू पर 57 मैच खेले जाएंगे, जिनमें दक्षिण अफ्रीका के 8, जिम्बाब्वे के 3 और नामीबिया का 1 मैदान शामिल है। यह नामीबिया के लिए पहला मौका होगा जब वह पुरुषों के सीनियर विश्व कप मैचों की मेजबानी करेगा।

भुवनेश्वर को इन कारणों से शायद ही 2027 एकदिवसीय विश्वकप में जगह मिले

मुम्बई। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी-20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में वापसी होने के बाद से ही अब ये अटकलें लगायी जा रही हैं कि भुवनेश्वर को अगले साल होने वाले एकदिवसीय विश्वकप के लिए भी अवसर मिल सकता है। भुवनेश्वर के प्रशंसकों का मानना है कि अगर वह चार साल के बाद वापसी करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो उनकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी। हालांकि क्या वास्तव में भुवनेश्वर 2027 विश्व कप टीम का हिस्सा बन पाएंगे, इसकी संभावना इन प्रमुख कारणों से बेहद कम है।



इससे सबसे बड़ी बाधा ये है कि भुवनेश्वर कुमार की उम्र 2027 तक 37 वर्ष हो जाएगी, जो उन्हें हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरुर्र बराड़ जैसे युवा और उभरते हुए तेज गेंदबाजों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में पीछे कर देती है। भले ही जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे अनुभवी गेंदबाजों को तीसरे या चौथे तेज गेंदबाजी पार्टनर की आवश्यकता हो पर बढ़ती उम्र और युवाओं की ऊर्जा के सामने भुवी के लिए जगह बनाना आसान नहीं होगा। जहां हर्षित राणा चोट से जूझ रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा की फिटनेस पर सवालिया निशान हैं, और गुरुर्र बराड़ के पास अनुभव की कमी है, वहीं भुवी को भी यह मानना होगा कि एकदिवसीय प्रारूप की लंबी अवधि के लिए उनका

शरीर और फॉर्म कितना तैयार है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण लंबे स्पेल फेंकने की क्षमता है। अनुभव के आधार पर ही किसी खिलाड़ी को विश्व कप टीम में शामिल करना चयनकर्ताओं की रणनीति का हिस्सा नहीं होगा। भुवनेश्वर कुमार लंबे समय से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर हैं और साल में केवल तीन महीने ही सक्रिय रहते हैं, मुख्य रूप से आईपीएल या घरेलू टी20 लीग में चार ओवर के स्पेल फेंकते हैं। ऐसे में, यह एक बड़ी चुनौती होगी कि क्या वह 10 ओवर के वनडे स्पेल को उतनी ही दक्षता और निरंतरता के साथ फेंक पाएंगे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट से उनकी दूरी और लंबे-लंबे स्पेल फेंकने के लिए शरीर की क्षमता पर भी संदेह बना हुआ है।

अंत में, उनके एकदिवसीय रिकॉर्ड और विश्व

कप के आयोजन स्थल पर विचार करना आवश्यक है। भुवी ने भारत के लिए 121 एकदिवसीय मैचों में 35.11 के औसत और 5.08 की इकॉनमी से 141 विकेट लिए हैं। ये आंकड़े खराब नहीं कहे जा सकते, लेकिन विश्व कप के लिए हालिया प्रदर्शन और विशेष परिस्थितियों में प्रदर्शन अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। भुवनेश्वर कुमार ने अपना आखिरी एकदिवसीय मैच जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जहां उनका प्रदर्शन 0/64 और 0/67 रहा था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 16 एकदिवसीय मैचों में उनका औसत 57.53 रहा है और उन्होंने केवल 15 विकेट ही लिए हैं। 2027 का एकदिवसीय विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना है, ऐसे में दक्षिण अफ्रीकी परिस्थितियों में उनका कमजोर रिकॉर्ड उनकी राह में एक बड़ी बाधा बन सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी-20 श्रृंखला भुवी के लिए खुद को साबित करने का एक महत्वपूर्ण मंच होगा। भारत 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक न्यूजीलैंड में पांच टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा, जिसके बाद वनडे और टेस्ट श्रृंखलाएं भी होंगी। इस खर्वांड में श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। हालांकि, इन मैचों में उनका प्रदर्शन ही यह तय करेगा कि वह 2027 विश्व कप की दौड़ में कितने प्रतियोगी रह पाते हैं और क्या चयनकर्ता उन पर दांव लगाने का जोखिम उठाएंगे।

आईपीएल के लिए सभी टीमों ने अपने कोच तय किये

मुम्बई। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अगले सत्र के लिए सभी 10 फ्रैंचाइजी टीमों ने अपने के मुख्य कोच तय कर लिए हैं जिससे लीग के लिए बेहतर तरीके से तैयारी की जा सके। इस के तहत ही पूर्व भारतीय कप्तान सोरब गांगुली को दिल्ली कैपिटल्स ने नया मुख्य कोच बनाया है, जबकि पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को चेन्नई सुपर किंग्स की कोचिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन बदलावों के साथ, फ्रैंचाइजी अब अपनी नीलामी की रणनीति बनाते और मजबूत टीमों तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। दिल्ली कैपिटल्स, जो आईपीएल इतिहास में अभी तक एक भी खिताब नहीं जीत पाई है, ने अपने कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव करते हुए सोरब गांगुली को यह महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी है। गांगुली फ्रैंचाइजी के साथ पहले से ही जुड़े हुए थे, उन्होंने डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के पद पर कार्य किया था। वह हेमंग बदानी का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2025 में हेड कोच का पद संभाला था। गांगुली का अनुभव और नेतृत्व दिल्ली की टीम को पहली ट्रॉफी जीतने की दिशा में प्रेरित कर सकता है। वहीं दूसरी ओर, चार बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने भी अपने प्रतिष्ठित कोचिंग स्टाफ में बदलाव किया है। उन्होंने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान को नया हेड कोच नियुक्त किया है। जहीर खान ने लंबे समय से टीम के साथ रहे स्टीफन फ्लेमिंग का स्थान लिया है, जिन्होंने सीएसके को कई सफलताएं दिलाई हैं।

अब लॉस एंजिल्स ओलंपिक पर है हॉकी टीम की नजर: कोच फुल्टन

नई दिल्ली। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब अपनी निगाहें लॉस एंजिल्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों पर टिका दी हैं। मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने कहा है कि इसके लिए लिए अभी से विस्तृत रणनीति बनायी जाएगी। फुल्टन का मानना है कि भले ही आलंपिक अभी दूर लग रहा हो, लेकिन समय तेजी से बीत जाता है और तैयारियों में कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती, इसलिए अभी से सही शेड्यूल और तैयारी का रोडमैप तैयार करना आवश्यक है। कोच फुल्टन ने कहा कि अभी ओलंपिक में दो साल है पर ये अधिक समय नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में टीम का मुख्य फोकस एक सटीक शेड्यूल और दीर्घकालिक योजना तैयार करने पर है। इसमें आगामी दो साल, एक साल और छह महीने की तैयारी के बड़े चरणों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा, ताकि हर कदम सोच-समझकर आगे बढ़ाया जा सके और ओलंपिक के लिए टीम को सर्वोत्तम स्थिति में लाया जा सके।

टीम संरचना के संबंध में, फुल्टन ने संकेत दिया कि हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) के समापन के बाद टीम में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते



हैं। उनका लक्ष्य अनुभवी खिलाड़ियों के मजबूत समूह के साथ युवा और उभरती प्रतिभाओं को एकिकृत करके एक संतुलित और गतिशील टीम तैयार करना है। उन्होंने विशेष रूप से भारतीय ए टीम और अंडर-21 टीम में मौजूद अभूतपूर्व प्रतिभा का जिक्र किया, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। फुल्टन का मानना है कि युवा जोश और अनुभवी खिलाड़ियों का ज्ञान एक मजबूत नींव तैयार करेगा जो टीम को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। फुल्टन ने कहा, हमारे पास अनुभवी खिलाड़ियों का एक अच्छा समूह है और साथ ही कई प्रतिभावान युवा

खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने आगे बताया कि हॉकी इंडिया लीग के बाद अगले दो-तीन महीनों में, हम सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बारीक नजर रखेंगे, एक नई टीम का चयन करेंगे और पूरी नई ऊर्जा के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। यह प्रक्रिया युवा खिलाड़ियों को उच्च-स्तर के खेल का अनुभव प्रदान करने और उन्हें विश्व के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ताकि वे बड़े टूर्नामेंटों के दबाव को झेलने में सक्षम हो सकें। कोच ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत अब केवल एशिया में अपना दबदबा बनाए रखने तक सीमित नहीं रहना चाहता।

कारोबार

अमेजन में फिर छंटनी की गाज

ई-कॉमर्स दिग्गज ने वैश्विक स्तर पर 1,000 कर्मचारियों को निकाला, भारत में भी असर

नई दिल्ली। दुनिया की अग्रणी ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी दिग्गज कंपनी अमेजन ने अपने कॉर्पोरेट ढांचे को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से छंटनी के एक और दौर की शुरुआत की है।



रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस ताजा बर्कफोर्स रिडक्शन में वैश्विक स्तर पर अमेरिका, भारत

और ब्रिटेन में काम करने वाले 1,000 से कम व्हाइट-कॉलर (कॉर्पोरेट) कर्मचारियों को नौकरी

से निकाला गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कंपनी का प्रमुख 'ग्राइम बिग डील डेज' शॉपिंग

इवेंट चल रहा था। भारत और ब्रिटेन में प्रभावित कर्मचारियों को आंतरिक स्लैक चैनलों के माध्यम से इस फैसले की जानकारी मिली है। अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच लगभग 30,000 कॉर्पोरेट नौकरियां खत्म करने के बाद अमेजन द्वारा किया गया यह नया कदम दशाता है कि वैश्विक टेक क्षेत्र में पुनर्गठन की प्रक्रिया अभी पूरी तरह से थमी नहीं है।

छंटनी में कौन से विभाग और कर्मचारी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं?

अमेजन की ओर से की गई यह नई कटौती मुख्य रूप से कंपनी के 'स्टोर्स' बिजनेस पर केंद्रित है, जो इसके मूल ई-कॉमर्स ऑपरेशंस की देखरेख करता है। रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राहक सेवा और सेलिंग पार्टनर सर्विसेज में कार्यरत टीम इस कटौती से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं, हालांकि अन्य टीमों पर भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई गई है। अमेजन के प्रवक्ता ने रॉयटर्स द्वारा उद्धृत बयान में इन कटौतियों की पुष्टि करते हुए कहा कि ये स्टोर्स डिवीजन के भीतर

सीमित संख्या में भूमिकाओं को समायोजित करने का हिस्सा है। प्रवक्ता के अनुसार, हमने अपने स्टोर्स बिजनेस के कुछ हिस्सों में बदलाव किया है क्योंकि हमारा मानना है कि यह ढांचा हमारी प्राथमिकताओं को पूरा करने में हमें बेहतर ढंग से सक्षम बनाएगा। प्रभावितों को सहायता के बारे में बताते हुए कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह इस बदलाव और पुनर्गठन से प्रभावित होने वाले सभी कर्मचारियों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।

विवक कॉमर्स का बाजार सात गुना बढ़ने का अनुमान

छोटे शहरों में बढ़ी पकड़; क्या बदलेगा खरीदारी का तरीका?

नई दिल्ली। देश के ई-कॉमर्स बाजार में विवक कॉमर्स मार्केट सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि खरीदारी का शक्तिशाली जरिया बन चुका है और तेजी से बदल रहा है। महानगरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी इसकी पैठ लगातार बढ़ रही है। गूगल और रेडसीर स्ट्रेटजी कंसल्टंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय विवक कॉमर्स मार्केट अगले पांच साल में वित्त वर्ष 2026 के लगभग 13 अरब डॉलर से सात गुना बढ़कर 90 अरब डॉलर (लगभग 867 हजार करोड़ रुपये) तक पहुंच सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह महानगरों में इसकी गहरी पैठ और टियर-2 व टियर-3 शहरों में ग्राहकों की तेजी से बढ़ती संख्या है। विवक कॉमर्स मार्केट, ऑनलाइन रिटेल का एक ऐसा मॉडल है, जिसमें ऑर्डर किए गए उत्पाद (जैसे किराने का सामान, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें) मात्र 10 से 30 मिनट के भीतर उसके घर पहुंचा दिए जाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2031 तक देशभर में हर महीने लेनदेन करने वाले यूजर्स की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो सकती है। इस दौरान होने वाली कुल बढ़ोतरी में अकेले महानगरों की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

टाटा समूह विवाद: सात ट्रस्टों ने दाखिल किए 84 कैविएट; नोएल-नेविल टाटा पर क्यों बढ़ा दबाव?

मुंबई। टाटा ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवाद के बीच सात ट्रस्टों ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के समक्ष कुल 84 कैविएट दायर किए हैं। इनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ट्रस्टों से जुड़े किसी मामले में चैरिटी कमिश्नर कोई आदेश देने से पहले संबंधित पक्षों की बात सुने।

सूत्रों के मुताबिक, इन कैविएट में नोएल टाटा और नेविल टाटा को कैविएटर बनाया गया है। टाटा ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाले सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) में शासन और फैसले लेने के अधिकार को लेकर विवाद बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में कैविएट दाखिल करने की वजह नोएल टाटा और नेविल टाटा के खिलाफ लगाए गए अलग-अलग आरोप बताए जा रहे हैं। टाटा ट्रस्ट ने फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर पहले ही सर रतन टाटा ट्रस्ट के कामकाज पर कुछ प्रतिबंध लगा चुके हैं। इसके चलते ट्रस्ट फिलहाल बैठक नहीं कर पा रहा है। यह रोक हटाने तक ट्रस्ट की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती। उधर, श्रीनिवासन ने नोएल टाटा की नियुक्ति और उनके स्थायी ट्रस्टी के रूप में बने रहने की जांच की मांग की है। यह भी सवाल उठाया है गया कि नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाने का आधार क्या था और वह इस पद पर कैसे बने हुए हैं।

जुड़े कुछ फैसलों में नोएल टाटा की भागीदारी और मतदान के अधिकार पर भी रोक लगाने की मांग की है। इसमें टाटा संस के निदेशकों, प्रतिनिधियों या प्रॉक्सी की नियुक्ति अथवा उन्हें निर्देश देने से जुड़े मामले शामिल हैं।

शेयर बाजार में गिरावट; सेंसेक्स 350 अंक लुढ़का, निफ्टी 22500 से नीचे

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक के सख्त मौद्रिक नीति के संकेत और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों इसका मुख्य कारण रही। विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी से भी बाजार का माहौल खराब हुआ। हालांकि, डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे मजबूत होकर 96.65 पर पहुंच गया।

शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स 357.67 अंक गिरकर 72,281.03 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 108.80 अंक की गिरावट के साथ 22,494.25 पर आ गया। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में आईटीसी, अदाणी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और इंटरनेट एक्सप्लोरन प्रमुख रूप से

नुकसान में रहीं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक, टेक महेंद्रा और इंफोसिस लाभ में रहे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2.02 फीसदी बढ़कर 102.2 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरेल पर पहुंच गया। बुधवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 6,121.37 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को अपनी बेंचमार्क रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50 फीसदी कर दिया। यह लगभग चार साल में पहली वृद्धि है। आरबीआई ने संकेत दिया कि निकट भविष्य में दर में कटौती की कोई संभावना नहीं है। इसके बजाय बढ़ती महंगाई, कमजोर रुपया और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण आगे और वृद्धि हो सकती है। आरबीआई की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर



बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। समिति ने अपनी नीतिगत स्थिति को रतटस्थ रखे से कैलिब्रेटेड टाइटनिंग

में बदल दिया। एनरिक मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोनुमुडी आर ने कहा कि आरबीआई की नीति को कमजोर

बाद भारतीय शेयरों के लिए दृष्टिकोण सतर्क बना हुआ है। रुपया गुरुवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे बढ़कर 96.65 पर पहुंच गया। यह भारतीय रिजर्व बैंक के संभावित हस्तक्षेप के कारण हुआ। हालांकि, रुपया लगातार व्यापक आर्थिक चुनौतियों के कारण दबाव में है। इनमें वैश्विक डॉलर की मजबूती और ब्रेंट क्रूड की ऊंची कीमतों शामिल हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में भी तीन हफ्तों में 50 अरब अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई है। फाइनेक्स के ट्रेजरी प्रमुख और कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंषाली के अनुसार, डॉलर की मजबूत कंपोरेट आयातक मांग और सुरक्षित-निवेश पूंजी के बदलाव ने आरबीआई की नीति को कमजोर

किया। गवर्नर ने रुपये को उसके सही मूल्य पर लाने में मदद करने का आश्वासन दिया है। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोरसो, जापान का निक्केई 225 इंडेक्स, शंघाई का एस.एस.ई. कंपोजिट इंडेक्स और हैंग सेंग इंडेक्स सभी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। बुधवार को अमेरिकी बाजार भी निचले स्तर पर बंद हुए थे। एच.एस.टी. वेल्थ के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिसिल्वन राधाकृष्णन ने कहा कि अब केवल आरबीआई की दर वृद्धि ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक सख्त घरेलू और वैश्विक मौद्रिक नीतियों की संभावना भी एक बड़ी चिंता है। फेडरल रिजर्व के फिनट्स भी अमेरिकी दर वृद्धि की ओर इशारा करते हैं।

महत्वपूर्ण ख़बर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारतीय वायु सेना दिवस के वीर योद्धाओं को शुभकामनाएं दीं

■ भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समस्त वीर योद्धाओं को भारतीय वायु सेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि भारत माता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर, साहस और शौर्य की मिसाल, वायु सेना के शूरवीरों की वीरता एवं कर्तव्यनिष्ठा पर सभी देशवासियों को गर्व है। उनके पराक्रम, समर्पण और अदम्य साहस से ही हमारा आकाश सुरक्षित है।

मुख्यमंत्री ने मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की

■ भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि मुंशी प्रेमचंद ने गोदान, गबन, निर्मला और बूढ़ी काकी जैसी अमूल्य रचनाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत का यथार्थ चित्रण कर जन-जन की संवेदनाओं को प्रखर अभिव्यक्ति प्रदान की। साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद का अद्वितीय योगदान युगों-युगों तक अमिट रहेगा।

मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध अभिनेता पद्मश्री नाना पाटेकर के निधन पर दुःख व्यक्त किया

■ भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय सिनेमा और रंगमंच के प्रतिष्ठित कलाकार 'पद्म श्री' नाना पाटेकर के निधन पर दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि नाना पाटेकर का जाना कला जगत के लिए अग्रणीय क्षति है। अपने बहुआयामी व्यक्तित्व और उत्कृष्ट योगदान से उन्होंने असंख्य लोगों के हृदय में विशेष स्थान बनाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महकाल से दिवंगत की आत्मा को अपने श्रौचणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजन तथा प्रशंसकों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

भोपाल में सिद्धांता अस्पताल सील: जी+1 की मंजूरी पर खड़ी कर दी चार मजिलें, लाइसेंस रद्द; अब तोड़ने का नोटिस जारी

भोपाल। राजधानी में नियमों को ताक पर रखकर भवन खड़े करने और उनका मनमाना उपयोग करने वालों पर नगर निगम की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। एक दिन पहले दो केमिकल फैक्ट्रियों को सील करने के बाद बुधवार को भवन अनुज्ञा शाखा ने रेडक्रास सोसायटी स्थित सिद्धांता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को सील कर दिया। निगम के अनुसार, भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा इस भवन के लिए जी प्लस वन की अनुमति कामकाजी महिला छात्रावास के प्रयोजन से दी थी, लेकिन मीके पर निर्माण चार मंजिला मिला। यानी स्वीकृत से तीन मंजिल अधिक निर्माण कर दिया गया। ऊपर से उसी भवन में अस्पताल संचालित हो रहा था। निगम ने इसे स्वीकृत अधिभोग का उल्लंघन मानते हुए 21 अगस्त को नोटिस जारी किया था और 12 सितंबर को 24 घंटे का अंतिम नोटिस भी किया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन उच्च न्यायालय चला गया था। हालांकि, बाद में अस्पताल प्रबंधन ने न्यायालय से अपना आवेदन वापस ले लिया, जिसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया। स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण के चलते अब निगम प्रशासन अस्पताल की इमारत को तोड़ने की कार्रवाई भी कर सकता है। अतिरिक्त निर्माण को लेकर निगम ने नोटिस जारी कर दिया है। वहीं इससे पूर्व स्वास्थ्य विभाग की जांच में भी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर 19 गंभीर कमियां सामने आ चुकी हैं। इसके बाद सीएमएचओ कार्यालय ने अस्पताल का नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस निरस्त कर दिया था। निगम के अनुसार, भवन में फायर सेफ्टी नार्म्स के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं भी पूर्व में नहीं पाई गई थीं।

इनका कहना है
सिद्धांता अस्पताल के भवन को स्वीकृत उपयोग के विपरीत संचालित किए जाने पर सील किया गया है। साथ ही अतिरिक्त निर्माण को लेकर भवन स्वामी को नोटिस जारी किया गया है। नियमों के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

भुवन गुप्ता, उपायुक्त, नगर निगम

भोपाल। हाल ही में जारी हुए भोपाल विकास योजना-2047 के प्रारूप के बाद इस त्योहारी सीजन में रियल एस्टेट बाजार में खरीदारों की प्राथमिकता अब पहले जैसी नजर नहीं आ रही है। प्रारूप सामने आने के बाद हज़ारों में प्रॉपर्टी के और बेहतर विकल्प खुल गए हैं, जिसके चलते आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक का रुख तेजी से बदल रहा है।

विशेषज्ञ के अनुसार विकास योजना के प्रारूप के बाद बड़े निवेशक प्रस्तावित ग्रोथ कॉरिडोर में भविष्य देखकर प्रॉपर्टी खरीदेंगे। वहीं



भोपाल का रीजनल प्लान भी तैयार हो रहा है, जिसके चलते जबलपुर रोड से इंदौर की तरफ प्रस्तावित बायपास रोड की प्रॉपर्टी पर बड़े खरीदारों का खास रुझान देखने को मिलेगा। इसके अलावा शहर में बन रहे मेट्रो स्टेशनों के आसपास

असीमित एफएआर के फायदे के कारण भी यहां बड़े प्रॉपर्टी खरीदारों का दबदबा देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट और कोलार रोड की तरफ भी बढ़ेगा रुझान

मध्यम और दीर्घकालिक प्रॉपर्टी खरीदार के लिहाज से शहर के अन्य छोरों पर भी तेजी देखने को मिलेगी। कालोनाइजरो और जानकारों का मानना है कि मास्टर प्लान के प्रारूप ने खरीदारों के सामने विकास की

छिंदवाड़ा के चौरई में पावर प्लांट की जमीन पर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लगाने का विरोध



छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले की चौरई तहसील में करीब 38 साल पहले सरकार ने किसानों से जमीन लेकर पावर प्लांट बनाने के लिए अडानी ग्रुप को दी थी। किसानों का आरोप है कि जमीन के बदले नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन पावर प्लांट का काम शुरू नहीं हुआ। इस वजह से किसानों

को नौकरी नहीं मिली और उनकी जमीन भी बंजर हो गई। किसानों ने करीब आठ साल पहले विरोध शुरू किया और सरकार से जमीन वापस देने की मांग की। अब इसी जमीन पर पावर प्लांट की जगह अडानी ग्रुप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर

किसानों का कहना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने से पूरे इलाके में नुकसान होगा। इसलिए उन्हें उनकी जमीन वापस कर दी जाए और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को कैसिल किया जाए। किसानों की बढ़ी चिंता चौरई तहसील के ग्राम चौसरा में थर्मल पावर प्लांट के प्रस्तावित

निर्माण के विरोध में हिवरखेड़ी, चौसरा, धनौरा, डागावानी, पिपरिया और थावड़ी सहित आसपास के अन्य गांवों के किसान हैं। इन सभी ने सामूहिक रूप से क्षेत्र में न केवल न्यूक्लियर पावर प्लांट अपितु थर्मल और अन्य प्रकार के पावर प्लांट की स्थापना को लेकर असहमति व्यक्त की है।

38 वर्षों से भूमि पर किसानों का कब्जा
किसानों के अनुसार, भूमि के संबंध में पहले से न्यायालयीन प्रकरण भी विचाराधीन हैं और लगभग 38 वर्षों से भूमि पर किसानों का कब्जा चला आ रहा है। किसानों ने कहा कि शासन द्वारा भूमि का अधिग्रहण कागजों में किया गया। उन्हें न तो मुआवजा मिला और ना ही कोई अन्य हितलाभ। इस मामले का विधि एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार निराकरण किया जाना चाहिए।

धार में बिना भूमिपूजन, बिना प्रचार... छह घंटे में सुधरा अस्पताल का जर्जर मार्ग, समाजसेवियों ने 200 मीटर में कराया डामरीकरण

धामनोद (धार)
शासकीय अस्पताल परिसर का अंदरूनी मार्ग जो वर्षों से गड्ढों के कारण मरीजों के लिए परेशानी बना हुआ था, वह अब दुरुस्त हो गया है। नगर के कुछ समाजसेवियों ने मंगलवार रात करीब छह घंटे में 200 मीटर लंबे मार्ग का अपने स्तर पर डामरीकरण करा दिया। इस दौरान न कोई भूमिपूजन हुआ, न प्रचार और न ही काम कराने वालों ने अपना नाम सार्वजनिक किया। स्ट्रेचर ले जाने में होती थी दिक्कत



अस्पताल परिसर का यह मार्ग लंबे समय से जर्जर था। जगह-जगह गड्ढे होने से मरीजों को स्ट्रेचर से एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक ले जाने में दिक्कत होती थी। बरसात में गड्ढों में पानी भर जाने से स्थिति और खराब हो जाती थी। लेपहिया वाहन

तक चला काम
समाजसेवियों ने मरीजों की परेशानी को देखते हुए स्वयं पहल की। मंगलवार रात करीब 10 बजे डामरीकरण का काम शुरू हुआ, जो रातभर चला और सुबह चार

बजे तक पूरा कर लिया गया। बुधवार सुबह जब मरीज और स्वजन अस्पताल पहुंचे तो गड्ढों की जगह डामरीकृत सड़क देखकर वे हैरान रह गए। अस्पताल सूत्रों के अनुसार इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों

मरीज और उनके स्वजन गुजरते हैं। नए रास्ते से अब एंबुलेंस और स्ट्रेचर की आवाजाही आसान हो गई है।
पशासन ने सराहा, रखरखाव की कही बात
इस संबंध में संबंधित अधिकारियों ने कहा कि अस्पताल परिसर के अंदरूनी मार्ग के लिए हमने कई बार पत्राचार किया था, लेकिन बजट अभाव के कारण काम नहीं हो पा रहा था। समाजसेवियों द्वारा कराए गए इस कार्य से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अब अस्पताल प्रशासन द्वारा इस मार्ग के रखरखाव की जिम्मेदारी ली जाएगी। समाजसेवियों ने बताया कि अस्पताल आने वाले मरीजों को हो रही परेशानी देखी नहीं गई। इसलिए बिना किसी प्रचार के यह काम कराया गया है। उन्होंने आगे भी अस्पताल में साफ-सफाई

और अन्य जरूरी सुविधाओं में सहयोग करने की बात कही।
सेवा का उदाहरण बना धामनोद
अमतौर पर सार्वजनिक कार्यों में भूमिपूजन और प्रचार की होड़ रहती है। ऐसे में बिना नाम और प्रचार के कराया गया यह डामरीकरण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
इनका कहना है
समाजसेवी अस्पताल में आते-जाते रहते थे। वह देखते थे कि अस्पताल परिसर पहुंचने में सड़क का हिस्सा गड्ढों में तब्दील था, जिसे समाजसेवी ने रातों-रात सुधार सामग्री लाकर सड़क सुधरवा दी। उन्होंने इसे गुप्तदान कहकर नाम उजागर नहीं करने का निवेदन किया है।
कोर्ति बोराली
सीबीएमओ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामनोद

किसान की आय, फसल और पानी के हिसाब से तैयार होगी खाद, ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय बना रहा नया मॉडल

ग्वालियर। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के वैज्ञानिक किसानों की आर्थिक उन्नति, भूमि सुधार और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक कवोक्मेषी सोर्स बेस्ड कंपोस्ट मॉडल तैयार कर रहे हैं।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य अंचल के किसानों को उनकी स्थानीय फसलों, भूमि के प्रकार और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जैविक व प्राकृतिक खाद बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। खासबात यह है कि इन इस

मॉडल से बनने वाली कंपोष्ट खाद में न केवल मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम के अलावा अन्य 17 सूक्ष्म तत्व होंगे। जिससे किसानों की फसल को पूरा पोषण मिलेगा। साथ ही रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। साथ ही इन मॉडलों को बनाने में प्रयास किया जा रहा है कि कार्बन का उत्सर्जन शून्य हो। जिससे वातावरण भी स्वच्छ रहे। यदि कंपोस्ट बनाने का ये मॉडल अपने प्रयोग में सफल रहते हैं तो इन्हें किसानों को अपनाने के लिए बुलाया जाएगा।
किसान की जरूरत के मुताबिक होने माउल
एग्रीफोरेस्ट्री बेस्ड नेचुरल मॉडल: यह मॉडल कृषि और वानिकी का बेहतरीन समन्वय है।



इसमें खेतों और वृक्षों से मिलने वाले जैविक कचरे का उपयोग कर टिकाऊ कंपोस्ट तैयार की जाएगी।

यह मॉडल सभी किसानों के लिए होगा।
हाई-इनकम एग्री-हार्टी नेचुरल

फार्मिंग मॉडल: कृषि और उद्यानिकी फसलों (फल व सब्जियां) को ध्यान में रखकर तैयार यह मॉडल

व्यावसायिक खेती करने वाले किसानों की उच्च पोषण आवश्यकता को पूरा करता है। इस मॉडल उन किसानों के लिए अनुकूल होगा जो आर्थिक रूप से भी अधिक सक्षम हैं और उनके पानी की उपलब्धता है। क्लाइमेट-रिजिलिएंट सिस्टम मॉडल: यह मॉडल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जैसे अनियमित वर्षा या सूखे जैसी परिस्थितियों में भी मिट्टी में नमी और जैविक कार्बन बनाए रखने में सक्षम है। इस मॉडल से उन किसानों को फायदा मिलेगा जिनके पास फसलों की सिंचाई के लिए पानी कम है। कम पानी भी इस खाद वे वे अच्छा उत्पादन ले सकेंगे।
इन तीनों मॉडलों को किसान की वित्तीय क्षमता, वार्षिक आय

और उनके क्षेत्र में पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इससे छोटे, मध्यम और बड़े किसान अपनी आवश्यकता अनुसार सही मॉडल चुनकर कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली खाद बना सकेंगे। साथ ही किसानों के पास उपलब्ध

एग्री वेस्ट या एनीमल वेस्ट का भी उपयोग कर सकेंगे। इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता शून्य कार्बन उत्सर्जन है। कंपोस्ट बनाने की पारम्परिक प्रक्रियाओं में निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसों पर नियंत्रण कर पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाएगा।

क्या कहते हैं वैज्ञानिक

इस तकनीक से रासायनिक उर्वरकों पर किसानों की निर्भरता काफी कम होगी, जिससे खेती की लागत घटेगी। इसके साथ ही लगातार रासायनिक खादों के इस्तेमाल से खराब हो रही मिट्टी की जैविक उर्वरता और जल धारण क्षमता में सुधार होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन इन सोर्स बेस्ड मॉडल बनाने का प्रयोग सफल होता है तो इनका प्रदर्शन विभिन्न माध्यमों से किसानों के के सामने किया जाएगा। जिससे वे इन्हें अपना सकें।

डॉ. एकता जोशी
वैज्ञानिक व नोडल अधिकारी, आरवीएसकेवि